Drishti IAS

करेंट अफेयर्स राजस्थान

मार्च (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

राजस्थान **4**

- राष्ट्रीय विज्ञान दिवस- 2023 4
- राजस्थान साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका मधुमती का नियमित प्रकाशन 4
- प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिये 35 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल का अनुमोदन 5
- खाद्य पदार्थों की जाँच के लिये प्रदेश में जल्द खुलेगी रैफरल लैब 6
- नीमकाथाना में 33 केवी के तीन सब स्टेशनों को स्वीकृति 7
- शिक्षा मंत्री को सौंपा गया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकाड्र्स का सर्टिफिकेट 8
- रिन्यूबल एनर्जी कॉन्क्लेव 8
- गुलाबी नगरी के वैभव को संरक्षित करने हेतु ऑस हैरिटेज व पीडीकोर के बीच हुआ एम ओ यू 9
- मुख्यमंत्री ने विवाह सम्मेलनों के लिये बढ़ाई सहायता राशि 9
- राष्ट्रपति ने गायत्री देवी यादव को जल योद्धा श्रेणी से किया सम्मानित 10
- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वनस्थली विद्यापीठ व आरकैट के बीच हुआ एमओयू 10
- प्रदेश के 30 हज़ार विद्यार्थियों को मिलेगा 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना' का लाभ 11
- अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के तहत राजस्थान मिलेट्स कॉनक्लेव 2023 का आयोजन 11
- जयपुर में इंटरनेशनल राजस्थानी कॉनक्लेव का आयोजन किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन 12
- पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कार्मिकों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी 13
- पालनहार योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि में वृद्धि 13
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान 13
- जयपुर में स्थापित होगी बिहेवियरल लैब 15
- सीकर, अलवर, नागौर, भरतपुर एवं अजमेर में खोले जाएंगे पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र 15
- इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह 15
- राजस्थान मिलेट्स कान्क्लेव-2023 16
- पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) के लिये 14200 करोड़ रुपए स्वीकृत 17
- आईटी डे-2023 फेस्टिवल 17
- प्रदेश में संरक्षित वन क्षेत्र बढ़कर हुआ 3.92 प्रतिशत 18

नोट :

- पशुपालक सम्मान समारोह 19
- भारत सिंगापुर के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास 'बोल्ड कुरुक्षेत्र' जोधपुर में संपन्न 19
- 16 ज़िलों के 8 हज़ार 108 ग्राम अभावग्रस्त घोषित 19
- राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने हेतु समिति का गठन 20
- राजस्थान में 19 नए ज़िले, 3 नए संभाग बनेंगे 20
- मुख्यमंत्री द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ 21
- जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का उद्घाटन 21
- जामडोली में खुलेगा दिव्यांगजनों के लिये प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय 22
- राजस्थान एमएसएमई एक्ट-2023 विधेयक पारित 22
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना' 23
- राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 पारित 24
- राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 संशोधित रूप में पारित 24
- राज्य में 44 वेटलेंड्स के लिये ड्राफ्ट अधिसूचना जारी 25
- 'राजीव गांधी जल संचय योजना (आरजीजेएसवाई)' का द्वितीय चरण प्रारंभ 25
- चार दिवसीय संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का हुआ शुभारंभ 26
- 'अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया' पर कार्यशाला 27
- राजस्थान साहित्य अकादमी ने घोषित किये वर्ष 2022-23 के पुरस्कार 28
- उदयपुर एवं राजसमंद में बनेंगे केटल फीड प्लांट 29
- राष्ट्र स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग सम्मेलन 30
- राजस्थान साहित्य उत्सव (साहित्य कुंभ-2023) जोधपुर में शुरू 30
- बीकानेर में तीन दिवसीय किसान मेला शुरू 31
- राज्य में अब शॉप्स एवं डॉग ब्रीडर्स का पंजीयन अनिवार्य 31
- प्रतापगढ़ में 'पीपलखूंट हाइलेवल कैनाल'के लिये 2000 करोड़ रुपए स्वीकृत 32
- पन्नाधाय, अमरा जी भगत और केसरी सिंह बारहठ का बनेगा पेनोरमा 32
- राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के पुरस्कारों की घोषणा 33
- आईसीडीएस विभाग के आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों एवं शिशुपालना गृह कायकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि 34
- स्टेट जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की 57 वीं बैठक 34
- राजस्थान दिवस 2023 35
- जोधपुर में सूचना आयोग की बेंच स्थापित होगी 37

नोट :

राजस्थान

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस- 2023

चर्चा में क्यों ?

28 फरवरी, 2023 को राजस्थान के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जयपुर के शास्त्रीनगर में स्थापित क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र एवं विज्ञान उद्यान में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र के क्यूरेटर कैलाश मिश्रा ने बताया कि विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिये विभाग द्वारा 28 फरवरी से 15 मार्च तक प्रदेश के सभी ज़िलों में निजी शिक्षण संस्थाओं, महाविद्यालय, विद्यालय, अभियांत्रिकी विद्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।
- इनमें चमत्कारों की वैज्ञानिक व्याख्या पर प्रदर्शन, द्रव्य नाइट्रोजन के मनोरंजक प्रयोग, साइंस शो, विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान चित्रकला प्रतियोगिता, विज्ञान निबंध, विज्ञान क्विज, विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान वार्ता, स्लोगन राइटिंग, वाद विवाद जैसी प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएंगी।
- कार्यक्रम में आगामी 15 दिनों के लिये पूरे प्रदेश में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कार्यक्रमों के पोस्टर का विमोचन किया गया।
- उल्लेखनीय है कि नोबेल पुरस्कार विजेता सर सी वी रमन ने रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी, 1928 को की थी, इस दिवस को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- इस वर्ष की थीम 'वैश्विक कल्याण के लिये वैश्विक विज्ञान' (ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग) रखी गई है।
- कैलाश मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विभाग द्वारा पूरे जयपुर शहर के प्रमुख स्थानों पर सेल्फी प्वाइंट लगाए गए हैं। विभाग द्वारा यह नवाचार इसलिये किया गया है ताकि लोगों को विज्ञान की अवधारणाओं से जोड़ा जा सके और अंधविश्वासों से परे जागरूक किया जा सके।
- कार्यक्रम में राजस्थान विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ऋषि कुमार सिंघल ने बताया कि मात्र 18 वर्ष की उम्र में सर सी वी रमन का शोध पत्र प्रकाशित हुआ था। सागर की लहरों पर सूर्य के किरणों की अठखेलियाँ देखकर सी वी रमन के मन में विचार आया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि विज्ञान की एक महत्त्वपूर्ण घटना है और वे प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन में जुट गए।
- उन्होंने मात्र 200 रुपए की लागत से स्पेक्ट्रोमीटर का आविष्कार किया और स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से रमन प्रभाव ने उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करवाया।
- कार्यक्रम में राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी-2022, राष्ट्रीय विज्ञान नाटक उत्सव प्रतियोगिता- 2022, पश्चिम भारत विज्ञान मेला 2022-23, नेशनल चिल्ड्रन साइंस कॉन्ग्रेस 2022-23 के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।

राजस्थान साहित्य अकादमी की मासिक पत्रिका मधुमती का नियमित प्रकाशन

चर्चा में क्यों ?

28 फरवरी, 2023 को राजस्थान के कला, साहित्य एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने बताया कि राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा मासिक पत्रिका मधुमती का नियमित प्रकाशन किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- कला, साहित्य एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने बताया कि इस पत्रिका के 48 अंकों का प्रकाशन कर ई-बुक को अकादमी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

नोट :

- मधुमती के अंकों में देशभर के एवं राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकारों एवं महापुरूषों के लेख समाहित किये जाते हैं। इसके अलावा किसी विदेशी भाषा का लेख भी आया है तो उसका अनुवाद भी प्रकाशित किया गया है।
- डॉ. बी. डी. कल्ला ने बताया कि अकादमी द्वारा पुस्तक 'गांधी सबद निरंतर'का भी प्रकाशन किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि 28 जनवरी, 1958 में राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा अन्य भारतीय भाषाओं एवं विदेशी भाषाओं के साहित्य के अनुवाद के लिये वर्ष 2013 से 2017 के दौरान कोई कार्य नहीं किया गया है।

प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिये 35 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल का अनुमोदन

चर्चा में क्यों ?

1 मार्च, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में आर्थिक, सामाजिक विकास, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने, राज्य कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और संगठित अपराधों को नियंत्रित करने सहित 35 विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रिमंडल की बैठक में 'दी राजस्थान कंट्रोल ऑफ आर्गनाइज्ड क्राइम बिल-2023' का अनुमोदन किया गया।
  - इसमें जिसके विरुद्ध पिछले दस सालों में न्यायालय में एक से अधिक आरोप पत्र पेश किया गया हो एवं न्यायालय ने उस पर प्रसंज्ञान लिया हो, साथ ही जिसने संगठित अपराध गिरोह के सदस्य के रूप में कोई अपराध, जो संज्ञेय व तीन साल या अधिक अवधि के लिये दंडनीय हो, उस व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।
  - संगठित अपराध गिरोह में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का गिरोह, जिसके द्वारा संगठित रूप से अपराध कारित किया जाता है पर कार्रवाई की जाएगी।
  - इसमें पीड़ित की मृत्यु होने पर अपराधी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास एवं न्यूनतम एक लाख रुपए का अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। साथ ही आपराधिक षड़यंत्र, गिरोह के सदस्यों को शरण देने के लिये न्यूनतम पाँच साल का कारावास जो अधिकतम आजीवन कारावास हो सकेगा। साथ ही न्यूनतम पाँच लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
  - वहीं, संगठित अपराध से संपत्ति अर्जित करने पर न्यूनतम तीन साल का कारावास जो अधिकतम आजीवान कारावास हो सकेगा, का प्रावधान किया गया है। साथ ही लोक सेवक जिसने संगठित अपराध में सहयोग किया है, उसे अधिकतम तीन साल का कारावास और अर्थदंड देने का प्रावधान है।
- मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित अन्य महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव-
  - मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट को जोधपुर में स्थापित करने से संबंधित विधेयक का अनुमोदन किया है। इंस्टीट्यूट डीम्ड पब्लिक यूनिवर्सिटी की तरह कार्य करेगा। इसमें डिजिटल एवं वित्तीय प्रौद्योगिकी डोमेन में प्रमाण पत्र कोर्सेज तथा डिप्लोमा कोर्सेज की सुविधा उपलब्ध होगी।
  - मंत्रिमंडल ने राजस्थान राज्य वन नीति को स्वीकृति देने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से राज्य में वनों के सुव्यवस्थित विकास, प्रबंधन में सुविधा होगी एवं इससे राज्य में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा तथा रोज़गार के अनेक अवसर उत्पन्न होंगे।
  - मंत्रिमंडल ने राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के अतिरिक्त दोहन को रोकने तथा उनका सतत् रूप में उपयोग करने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन नीति का अनुमोदन किया।
  - मंत्रिमंडल ने राज्य में ई-वेस्ट को कम करने, उसके पुन: उपयोग तथा री-साईकिल करने और ई-वेस्ट से पर्यावरण को पहुँच रही क्षति को कम करने के उद्देश्य से 'ई-वेस्ट प्रबंधन नीति' का अनुमोदन किया है।
  - मंत्रिमंडल ने 1 जून, 2002 एवं इसके पश्चात् 2 से अधिक संतानों वाली विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को राज्य सरकार में नियुक्ति दिये जाने हेतु विविध सेवा नियमों में संशोधन को स्वीकृति दी है। साथ ही, 1 जून, 2002 या उसके पश्चात् 2 से अधिक संतान वाले कार्मिकों के पदोन्नति के संबंध में विविध सेवा नियमों में संशोधन किया गया है।

नोट :

- मंत्रिमंडल ने राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977 में संशोधन कर जलधारी/सफाईकर्त्ता/गड़रिया के पदों की शैक्षणिक योग्यता तथा पदनाम परिवर्तन किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इस निर्णय से जलधारी/सफाईकर्त्ता/गड़रिया के पदों को मर्ज कर इनका नवीन पदनाम 'पशु परिचारक'(एनिमल अटेंडेंट) हो सकेगा।
- मंत्रिमंडल ने राजस्थान मत्स्य राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 2012 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इससे मत्स्य अधीनस्थ सेवा के कार्य क्षेत्र में नहीं आने वाले पदों की भर्ती अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जा सकेगी।
- मंत्रिमंडल ने महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेन्स एंड सोशल साइंसेज विधेयक, 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया। इसके पारित होने पर जयपुर ज़िला मुख्यालय पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज संबंधी उच्च अधिगम (हायर लर्निंग) के क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्तरीय नवीन संस्थान की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा।
- मंत्रिमंडल ने जोधपुर में सिटी इनोवशन कलस्टर के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवशन हब (एआईओटी) स्थापित करने के लिये सेक्शन-8 कंपनी बनाने का अनुमोदन किया। इस निर्णय से प्रदेश के युवा, स्टार्टअप्स और उद्यमियों को फायदा मिलेगा और रोज़गार के अवसर सृजित होंगे।
- मंत्रिमंडल ने नगर पालिका सदस्य के विरूद्ध निर्वाचन से पूर्व की निर्हताओं के लिये कार्रवाई करने हेतु राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 39 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से राज्य सरकार को ऐसे नगर पालिका सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त हो सकेगा।
- मंत्रिमंडल ने जे.के. सीमेंट लिमिटेड को ग्राम-पारेवर, ज़िला-जैसलमेर में सीमेंट प्लांट की स्थापना हेतु 210 हैक्टेयर भूमि को आवंटित करने का निर्णय किया है। इस परियोजना में लगभग 5000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। परियोजना के स्थापित होने से 1000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष तथा 5000 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार मिलेगा।
- मंत्रिमंडल ने बाड़मेर ज़िले के ग्राम गुड़ामालानी में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना हेतु भूमि आवंटन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
- मंत्रिमंडल ने ग्राम नावाँ, ज़िला-नागौर में सरकारी भूमि पर ब्राडगेज डेडिकेटेड रेल लाइन के निर्माण का निर्णय लिया। इस डेडिकेटेड रेललाइन पर देश एवं विदेश में बनने वाले मध्य चल स्टॉक एवं आधारभूमि कंपोनेट टेस्टिंग व ट्रायल हो सकेंगे।
- मंत्रिमंडल ने जय मीनेष आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) विधेयक, 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किया। इस विधेयक के पारित होने पर निजी क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा।
- कैबिनेट बैठक में पूर्व बजट घोषणाओं की अनुपालना में ग्रेटर भिवाड़ी इंडस्ट्रीयल टाउनशिप क्षेत्र एवं मारवाड़ इंडस्ट्रीयल क्लस्टर नियोजन एवं इनके क्षेत्राधिकार को विस्तृत करके आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास करने का निर्णय लिया गया है।
- कैबिनेट बैठक में व्यावसायिक भवनों में ऊर्जा बचाने हेतु ऊर्जा दक्ष भवनों के निर्माण के लिये राजस्थान ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता व राजस्थान ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम-2023 का अनुमोदन किया गया। इससे भवन क्षेत्र में ऊर्जा की खपत में कमी आएगी। साथ ही, कार्बन-डाई-ऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आने से वातावरण को स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी।
- कैबिनेट बैठक में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पीटल सोसायटी तथा राजमेस के द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस एवं महिला विद्यार्थियों की तर्ज पर एमबीसी और ओबीसी वर्ग के नॉन क्रिमिलयर अभ्यर्थियों की सरकारी सीटों पर ट्यूशन फीस माफ करने का निर्णय लिया गया है।
- मंत्रिमंडल ने प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड वेलफेयर सोसायटी को बेघर डॉग्स के शेल्टर हाउस के लिये भूमि आवंटन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। यह भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना रामचंद्रपुरा में 1000 वर्गमीटर का नवसृजित भूखंड है।

खाद्य पदार्थों की जाँच के लिये प्रदेश में जल्द खुलेगी रैफरल लैब

चर्चा में क्यों ?

1 मार्च, 2023 को राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने विधानसभा में आश्वस्त किया कि खाद्य पदार्थों की जाँच के लिये राज्य में शीघ्र ही रैफरल लैब स्थापित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि राज्य खाद्य जाँच प्रयोगशाला एवं रैफरल लैब द्वारा खाद्य नमूनों की जाँच के लिये अलग-अलग पैरामीटर हैं। राज्य सरकार की ओर से देश भर में एक ही पैरामीटर निश्चित करने के लिये भी केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है।
- मंत्री परसादी लाल मीणा ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि राज्य प्रयोगशाला में खाद्य नमूनों की जाँच में अनसेफ आए नमूनों की जाँच रैफरल से कराई जा सकती है। वर्तमान में मुंबई, पुणे तथा मैसूर में रैफरल लैब स्थापित हैं।
- उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में सेफ तथा अनसेफ के पैरामीटर अलग-अलग हैं। राज्य प्रयोगशाला में अनसेफ 1202 नमूने रैफरल में भेजे गए थे, जहाँ उनमें से केवल 154 ही अनसेफ पाए गए। केंद्र सरकार द्वारा राज्य में भी रैफरल लैब की शीघ्र स्थापना का आश्वासन दिया गया है।
- इससे पहले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने विधायक सूर्यकांता व्यास के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाँच के लिये सरकारी प्रयोगशालाएँ स्थापित हैं। उन्होंने सरकारी प्रयोगशालाओं में गत चार वर्षों में लिये नमूनों तथा उनसे प्राप्त रिपोर्टों का वर्षवार एवं ज़िलेवार विवरण सदन के पटल पर रखा।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने उक्त रिपोर्ट से राज्य की खाद्य प्रयोगशालाओं द्वारा अनसेफ घोषित नमूनों से रेफरल लैब में भेजे जाने पर प्राप्त रेफरल से निर्णयों, अमानक एवं मानक माने गए नमूनों की वर्षवार एवं ज़िलेवार सूचना भी सदन के पटल पर रखी।
- परसादी लाल मीणा ने कहा कि खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा-46(4) में खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरूद्ध अपील संबंधित अभिहित पदाधिकारी को किये जाने के प्रावधान है। इन प्रावधानों के तहत संबंधित अभिहित अधिकारी द्वारा अपील किये जाने पर नमूनों की जाँच अभिहित अधिकारी द्वारा रेफरल प्रयोगशाला से करवाई जा सकती है। एफएसएसएआई द्वारा राज्य के लिये मैसूर, पूणे एवं नवी मुंबई तीन रैफरल लैब नियत की गई हैं।
- उन्होंने बताया कि प्रदेश की प्रयोगशाला व रैफरल प्रयोगशाला के नतीजो में भिन्नता का मुख्य कारण अलग-अलग पैरामीटर्स पर जाँच करना है एवं नमूनों की जाँच के उपरांत प्राप्त जाँच परिणामों के लिये जाँचकर्त्ता अधिकारी द्वारा अपनी राय देने के लिये प्राप्त परिणामों की व्याख्या भिन्न-भिन्न किया जाना भी एक कारण है।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में रैफरल लैब की स्थापना हेतु एफएसएसएआई नई दिल्ली को वर्क प्लान 2023-24 में एमओयू के अंतर्गत प्रस्ताव प्रेषित किये गए हैं।

नीमकाथाना में 33 केवी के तीन सब स्टेशनों को स्वीकृति

चर्चा में क्यों ?

2 मार्च, 2023 को राजस्थान के ऊर्जा राज्यमंत्री भँवरसिंह भाटी ने बताया कि प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र नीमकाथाना में 33/11 केवी के तीन सब स्टेशनों को स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

प्रमुख बिंदु

- ऊर्जा राज्यमंत्री भँवरसिंह भाटी ने बताया कि नीमकाथाना में 33/11 केवी जीएसएस डाबर का निर्माण इसी माह तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है तथा इसी विधानसभा क्षेत्र में 33/11 केवी सब स्टेशन मंडोली व कोला की नांगल का निर्माण आगामी वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है।
- उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र नीमकाथाना में नये 33/11 केवी सब स्टेशन के तीन प्रस्ताव डाबर, मंडोली एवं कोला की नांगल के प्राप्त हुए थे। इनमें से डाबर की स्वीकृति 16 मार्च, 2022 को तथा मंडोली एवं कोला की नांगल की स्वीकृति 25 फरवरी, 2023 को जारी की जा चुकी है।

नोट :

शिक्षा मंत्री को सौंपा गया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड्स का सर्टिफिकेट

चर्चा में क्यों ?

2 मार्च, 2023 को जयपुर के शिक्षा संकुल में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड्स, लंदन के इंडिया चैप्टर में राजस्थान के वाइस प्रेसीडेंट प्रथम भल्ला ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड्स का प्रमाण-पत्र सुपर्द किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड्स, लंदन की ओर से राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा गत वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती (19 नवंबर, 2022) पर 'नो बैग डे' के तहत 'चैस इन स्कूल एक्टिविटी'के नवाचार में 38 लाख 21 हज़ार 9 विद्यार्थियों की भागीदारी को सर्टिफाइड किया गया था।
- शिक्षा मंत्री डॉ. कल्ला के नाम संदेश में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड्स, लंदन के इंडिया चैप्टर द्वारा बताया गया है कि शिक्षा विभाग के इस इनीसिएटिव को उनके द्वारा अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसके तहत प्रदेश के सभी 33 ज़िलों में 57 हज़ार 462 स्कूलों में गत नवंबर माह के तीसरे शनिवार को 'नो बैग डे'का आयोजन किया गया।
- इस अवसर पर पूरे प्रदेश में 38 लाख 21 हज़ार 9 विद्यार्थियों ने दिमागी कसरत का खेल (शतरंज) खेला। एक ही दिन में एक साथ 38 लाख 21 हज़ार 9 विद्यार्थियों की शतरंज में भागीदारी ने राजस्थान के शिक्षा विभाग का नाम विश्व पटल पर स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज करा दिया।
- उल्लेखनीय है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड्स का दुनियां के सभी महाद्वीपों में ग्लोबल नेटवर्क है। इसके द्वारा विभिन्न विधाओं में वर्ल्ड रिकार्ड्स के माध्यम से प्रतिभा और क्षमता का आकलन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।
- कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में विभाग की टीम पूरी स्पिरिट के साथ शैक्षणिक स्तर में प्रगति एवं बच्चों के संर्वांगीण विकास की दिशा में कार्य कर रही है। इसी की बदौलत विभाग ने 'चैस इन स्कूल एक्टिविटी'सहित पाँच विश्व रिकार्ड बनाए हैं।
- इस अवसर पर स्कूल शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के स्कूलों में शतरंज को बढ़ावा देने के लिये शतरंज एसोसिएशन की ओर से उपलब्ध कराई गई अंग्रेजी एवं हिन्दी की चैस बुक्स को भी स्कूलों में भिजवाया जाएगा।

रिन्यूबल एनर्जी कॉन्क्लेव

चर्चा में क्यों ?

3 मार्च, 2023 को के जयपुर में आरआरईसीएल, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड तथा इकोनॉमिक टाइम्स के संयुक्त तत्वावधान में रिन्यूबल एनर्जी कॉन्क्लेव आयोजित हुआ।

प्रमुख बिंदु

- रिन्यूबल एनर्जी कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि राज्य सरकार की निवेश के अनुकूल नीतियों से राजस्थान आज अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है।
- उन्होंने बताया कि निवेशक राज्य में सौर ऊर्जा के साथ पवन ऊर्जा, हाईब्रिड संयंत्र और ग्रीन हाईड्रोजन परियोजनाएँ स्थापित करने के लिये आगे आ रहे हैं। राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा संयंत्रों के लिये जरूरी उपकरणों का निर्माण राजस्थान में ही करवाने के लिये प्रतिबद्ध है ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार भी सृजित हो सके।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में अपार संभावनाएँ हैं। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला (जोधपुर) में स्थित है। पूरे देश में अक्षय ऊर्जा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण वर्ष 2022 में राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया है एवं आरआरईसीएल को राष्ट्रीय स्तर पर अक्षय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है।
- कॉन्क्लेव के दौरान राज्य सरकार एवं निवेशकों के बीच एमओयू हस्ताक्षरित हुए। राज्य सरकार एवं टोरेंट पावर लिमिटेड के मध्य अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में हस्ताक्षरित हुए एमओयू से राज्य में 37 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश आएगा तथा 6150 रोज़गार सृजित होंगे।

नोट :

- इसके अलावा वेलस्पन न्यू एनर्जी लिमिटेड और राज्य सरकार के बीच अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में साइन हुए एमओयू से प्रदेश में 50 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश आएगा तथा 2250 लोगों को रोज़गार मिलेगा।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एनर्जी सेक्टोरल पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से ऊर्जा से संबंधित सभी जानकारियाँ एक ही स्थान पर मिल सकेगी। पोर्टल पर 11 विभागों के डेटा उपलब्ध हैं एवं इसे मुख्यमंत्री कार्यालय की आईटी टीम द्वारा बनाया गया है।

गुलाबी नगरी के वैभव को संरक्षित करने हेतु ऑस हैरिटेज व पीडीकोर के बीच हुआ एम ओ यू

चर्चा में क्यों ?

3 मार्च, 2023 को राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित करने हेतु जयपुर में पीडीकोर, जेडीए, नगर निगम जयपुर हैरिटेज, जयपुर स्मार्ट सिटी लि. व नवागंतुक आस्ट्रेलिया के सहभागी संगठन ऑस हैरिटेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में ऑस हैरिटेज और पीडीकोर के बीच एक एमओयू साईन हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- इस एमओयू के तहत ऑस हैरिटेज संगठन जयपुर शहर की पुरा संपदा के संरक्षण व संवर्द्धन हेतु म्युचुअल रुचि के कोर क्षेत्र में आधुनिक व परंपरागत प्राचीन विधाओं का इस्तेमाल करते हुए सेवाएँ प्रदान करेगा।
- उल्लेखनीय है कि राजा सवाई जयसिंह द्वारा 35-40 चालीस हज़ार लोगों के लिये खुशहाली के साथ निवास करने हेतु 1727 में बसायी गई गुलाबी नगरी जयपुर जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत व 2015 में क्राफ्ट सिटी के रूप में घोषित किया जा चुका है।
- कार्यशाला के समापन सत्र में जयपुर विरासत फाउंडेशन की अध्यक्ष व सिटी पैलेस की डायरेक्टर रीमा हूजा ने कहा कि शहर की विरासत के साथ आबोहवा को बचाने हेतु बच्चों को भी हैरिटेज वारियर्स बनाना होगा।
- नगरीय विकास एवं आवासन हेतु राजस्थान सरकार के सलाहकार जी.एस. संधू ने ऑस हैरिटेज के अध्यक्ष व प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह व यूनेस्को विश्व विरासत जयपुर डेवलपमेंट प्लान पर केंद्रित पुस्तक भेंट की।

मुख्यमंत्री ने विवाह सम्मेलनों के लिये बढ़ाई सहायता राशि

चर्चा में क्यों ?

4 मार्च, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलनों को प्रोत्साहन देने के लिये अनुदान राशि को बढ़ाया है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब प्रति जोड़ा 25 हज़ार रुपए दिये जाएंगे। इसमें नववधू को 21 हज़ार रुपए और संस्था को 4 हज़ार रुपए का अनुदान मिलेगा। यह राशि 1 अप्रैल, 2023 से संपन्न विवाह सम्मेलनों को देय होगी।
- विदित है कि वर्तमान में यह राशि क्रमश: 15 हज़ार और 3 हज़ार रुपए अर्थात् कुल 18 हज़ार रुपए दी जा रही है।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामूहिक विवाह जैसी सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाने, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को रोकने और अनावश्यक व्यय को कम करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुये बजट 2023-24 में अनुदान राशि बढ़ाने संबंधित घोषणा की गई है।
- मुख्यमंत्री की ओर से वर्ष 2023-24 में सहायता राशि के रूप में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे लगभग 4000 जोड़ों को सामूहिक विवाह अनुदान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
- उन्होंने सामूहिक विवाह आयोजन में विभिन्न समाज, जाति एवं धर्म के परिवारों के शामिल होने पर आयोजकों को 10 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि देने पर सहमति दी है। 'अनेकता में एकता' की भावना को साकार कर कम से कम 25 जोड़ों के विवाह के आयोजन पर यह राशि मिलेगी। इसमें लगभग 20 संस्थाओं को 2 करोड़ रुपए की सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है।

नोट :

राष्ट्रपति ने गायत्री देवी यादव को जल योद्धा श्रेणी से किया सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

4 मार्च, 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 'स्वच्छ सुजल शक्ति' सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में जल महिला की भूमिका निभा रही स्वयंसेवी गायत्री देवी यादव को जल योद्धा श्रेणी से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- गायत्री देवी को यह पुरस्कार राजस्थान के जयपुर के सांभर ब्लॉक इलाके में फार्म पॉन्ड बनाने के लिये ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किये गए उत्कृष्ट कार्यों के लिये सम्मानित किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि गायत्री देवी यादव ने पिछले कई वर्षों से जयपुर की ग्राम चेतना केंद्र संस्था के साथ मिलकर सांभर ब्लॉक के करीब 68 गांव में 65 महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर वर्षा जल संचयन और संरक्षण के लिये उत्कृष्ट कार्य किये तथा ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को जल साक्षर बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
- ग्राम चेतना केंद्र संस्था के सदस्य बंसी लाल मीणा ने बताया कि गायत्री देवी यादव ने महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से वर्षा जल के संचयन और स्वच्छ जल प्रबंधन के लिये राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने में मदद करने का काम किया।
- उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में फार्म पॉन्ड (तलाई) के माध्यम से वर्षा जल को एकत्रित करके उसको पीने और खेती में उपयोग करने लायक बनाने तथा बेहतर जल प्रबंधन करने के लिये ग्रामीणों को प्रशिक्षित किया।
- गायत्री देवी द्वारा ग्रामीण महिलाओं को शुद्ध पीने के पानी तथा संचित वर्षाजल से दूसरी फसल लेने के लिये प्रशिक्षित करने के महत्त्वपूर्ण कामों से ग्रामीण इलाकों में परिवारों का पलायन रुका तथा उनकी आमदनी में वृद्धि हुई, इससे ग्रामीण महिलाओं को सम्मानपूर्ण जीवन जीने का मौका मिला।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वनस्थली विद्यापीठ व आरकैट के बीच हुआ एमओयू

चर्चा में क्यों ?

9 मार्च, 2023 को राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (आरकैट) द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में आरकैट व वनस्थली विद्यापीठ के मध्य एक एमओयू हुआ, जिसके तहत उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आरकैट वनस्थली के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को

नोट :

ट्रेनिंग उपलब्ध कराएगा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने के इच्छुक विद्यार्थियों को अपने औद्योगिक भागीदारों के साथ सहयोग प्रदान करेगा।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम में आरकैट के औद्योगिक भागीदार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब द्वारा ग्रामीण एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया।
- इस अवसर पर मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने कहा कि राजस्थान में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आईटी आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी अंग्रेज़ी माध्यमिक स्कूल, महिलाओं की सेहत से जुड़ी आईएम शक्ति उड़ान योजना तथा मुफ्त जाँच व दवाई योजना पूरे देश में मिसाल हैं।
- मुख्य सचिव ने बताया कि राजस्थान आईटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। राज्य की जन आधार योजना, इनक्यूबेशन सेंटर, डाटा सेंटर आदि इसके विशिष्ट उदाहरण हैं, जिन पर पूरा देश गर्व कर रहा है। आरकैट उच्च श्रेणी की कंपनियों के साथ एमओयू साइन करके बेहतरीन फिनिशिंग स्कूल के रूप में उभरा है।
- इस अवसर पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी आयुक्त व आरकैट के एमडी आशीष गुप्ता ने बताया कि आरकैट 70 से अधिक रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन आदि के क्षेत्रों में कोर्सेज का संचालन करता है व जल्द ही हर संभाग मुख्यालय में आरकैट शुरू कर दिया जाएगा।
- आरकैट की कार्यकारी निदेशक ज्योति लुहाडिया ने जानकारी दी कि आरकैट इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के साथ ही सामान्य स्नातक, महिलाओं के लिये भी अवसर उपलब्ध करा रहा है। आगामी सत्रों में माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियाँ भी आरकैट के साथ जुड़ेंगी।

प्रदेश के 30 हज़ार विद्यार्थियों को मिलेगा 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना' का लाभ

चर्चा में क्यों ?

9 मार्च, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना'के अंतर्गत लाभान्वितों की संख्या 15 हज़ार से बढ़ाकर 30 हज़ार करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी प्रदान की। इस योजना के लिये मुख्यमंत्री ने 56.40 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान का अनुमोदन किया है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश के आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये नि:शुल्क गुणवत्तापूर्ण कोचिंग प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध होंगे।
- उल्लेखनीय है कि राज्य के कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्सेज एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की नि:शुल्क तैयारी कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई थी।
- आशा के अनुरूप योजना की सफलता को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में लाभार्थियों की संख्या 10 हज़ार से बढ़ाकर 15 हज़ार की गई थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में बढ़ाकर 30 हज़ार कर दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के तहत राजस्थान मिलेट्स कॉनक्लेव 2023 का आयोजन

चर्चा में क्यों ?

9 मार्च, 2023 को प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी दिनेश कुमार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के तहत राज्य में 13 व 14 मार्च, 2023 को राजस्थान मिलेट्स कॉनक्लेव का आयोजन राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, दुर्गापुरा जयपुर में किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी दिनेश कुमार ने बताया कि मिलेट्स उत्पादकों, कृषि व्यवसायी, स्टार्टअप, एफ.पी.ओ., स्वयंसेवी संस्था, कृषि वैज्ञानिक एवं कृषि अधिकारियों के सहयोग से यह आयोजन किया जा रहा है। इस कॉनक्लेव में मिलेट्स स्टार्टअप एवं कृषि प्रसंस्करण के 100 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे।

नोट :

- सचिव दिनेश कुमार ने बताया कि बाजरा के क्षेत्र एवं उत्पादन में राजस्थान का देशभर में प्रथम स्थान है। देश में बाजरा क्षेत्रफल में राजस्थान का हिस्सा 57.10 प्रतिशत है तथा उत्पादन में 41.71 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। इसी तरह राष्ट्र में ज्वार के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में राज्य का तीसरा स्थान है।
- उन्होंने बताया कि राजस्थान में मिलेट्स प्रोत्साहन के लिये मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में राजस्थान मिलेट्स मिशन की घोषणा की गई, जिसके तहत बाजरा व ज्वार की खेती के प्रोत्साहन, उत्पादन में वृद्धि, घरेलू खपत को बढ़ावा देने एवं मुख्य संवर्धन के लिये कई रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं।
- इसी के तहत बीज मिनिकिट्स का वितरण किया गया है। साथ ही उत्पादन में वृद्धि फसलोत्तर प्रबंधन एवं मूल्य संवर्धन के लिये जोधपुर में मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है।
- प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि मिलेट्स की खपत को बढ़ाने के लिये इसके स्वास्थ्यप्रद लाभों को प्रचारित करने व मिलेट्स के उत्पादों को लोकप्रिय बनाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के अंतर्गत पूरे राज्य में वर्षभर आयोजनों की कार्य योजना बनाई गई है।
- उन्होंने बताया कि मिलेट्स पोषण महत्त्व पर राज्यस्तरीय सेमिनार एवं एग्रो प्रोसेसिंग पर कॉनक्लेव आयोजित किये जा रहे हैं, जिनमें मिलेट्स उत्पादक, कृषि व्यवसायी, स्टार्टअप, एफ.पी.ओ., स्वयंसेवी संस्था, कृषि वैज्ञानिक और अधिकारियों के मध्य संवाद के माध्यम से ठोस रणनीति विकसित की जा रही है।
- उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत आमजन को बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटंकी और सावा जैसे अनेक मिलेट्स के पोषक महत्त्व एवं स्वास्थ्य के लिये फायदों के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही इनके उत्पादन, उत्पादकता एवं विपणन के अवसरों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

जयपुर में इंटरनेशनल राजस्थानी कॉनक्लेव का आयोजन किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन

चर्चा में क्यों ?

9 मार्च, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23-24 सितंबर, 2023 को जयपुर में इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। उद्योग विभाग एवं राजस्थान फाउंडेशन के तत्त्वाधान में होने वाले इस बृहद् आयोजन के लिये मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों को एकसूत्र में बांधने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 के बजट में इंटरनेशनल राजस्थानी कॉनक्लेव के आयोजन की घोषणा की थी।
- सितंबर में आयोजित होने वाले इस दोदिवसीय कॉनक्लेव में राजस्थानी गौरव, साहित्य, व्यापार, परंपरा, संगीत, कला, संस्कृति, सामाजिक कल्याण, उद्यम, खान-पान एवं मनोरंजन आदि विषयों पर दिलचस्प सत्रों का आयोजन होगा।
- इसमें उद्यमशीलता एवं निवेश के अवसरों पर एक विशेष सत्र शामिल होगा। इसमें विश्व भर से प्रवासी उद्यमी भाग लेंगे। एनआरआर नीति में घोषित प्रवासी सम्मान पुरस्कार का शुभारंभ भी इसी कॉनक्लेव में किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2000 में राजस्थानी डायस्पोरा का महत्त्व समझते हुए मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व में पहली बार इंटरनेशनल राजस्थानी कॉनक्लेव का आयोजन हुआ था। केवल अपने डायस्पोरा के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना उस समय केंद्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार के लिये एक अनूठी पहल थी। इसी तर्ज़ पर वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया था। अन्य राज्यों ने भी इस मॉडल को अपनाया है।
- पिछले तीन वर्षों में प्रवासी राजस्थानियों के साथ संबंध मज़बूत करने में राजस्थान फाउंडेशन की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण रही है। फाउंडेशन नियमित रूप से प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करवाता रहा है। कोविड महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भी राजस्थान फाउंडेशन ने प्रवासियों की सहायतार्थ बड़ी भूमिका निभाई।

नोट :

पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कार्मिकों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों ?

10 मार्च, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेवानिवृत्त कार्मिकों के सेवा में पुनर्नियोजित होने पर मिलने वाले मासिक समेकित पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- उक्त प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 की पे-मैट्रिक्स के पे-लेवल के प्रथम सैल की 50 प्रतिशत राशि तथा उस पर विद्यमान महँगाई-भत्ते 38 प्रतिशत की राशि को जोड़कर 100 के गुणक में समेकित पारिश्रमिक राशि निर्धारित की गई है।
- इससे मासिक समेकित पारिश्रमिक राशि की दरें लगभग दोगुनी हो गई हैं।
- मुख्यमंत्री के इस निर्णय से पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कार्मिकों को बढ़ी हुई मासिक समेकित पारिश्रमिक राशि मिल सकेगी। इससे एक तरफ उनकी आय में वृद्धि होगी, वहीं राज्य सरकार को भी सेवानिवृत्त कार्मिक सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगे।
- उल्लेखनीय है कि लगभग 5 वर्षों बाद पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कार्मिकों की समेकित पारिश्रमिक राशि में बढ़ोतरी की गई है।

पालनहार योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

10 मार्च, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश के 6.5 लाख से अधिक बच्चे लाभान्वित होंगे।

प्रमुख बिंदु

- प्रस्ताव के अनुसार, अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिये प्रतिमाह मिलने वाली 500 रुपए की सहायता राशि को बढ़ाकर 750 रुपए तथा 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग को मिलने वाली 1000 रुपए की सहायता राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है।
- सहायता राशि में यह वृद्धि 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगी। इसके क्रियान्वयन से राज्य सरकार पर लगभग 411 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2023-24 में की गई घोषणा के संबंध में इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई है।
- राज्य सरकार द्वारा संचालित पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ श्रेणी के बच्चों को 1500 एवं 2500 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। इससे अब अन्य श्रेणी के बच्चों को भी अधिक सहायता राशि का लाभ मिलेगा।
- उल्लेखनीय है कि इस योजना में 18 वर्ष तक के अनाथ बच्चों, निराश्रित पेंशन की पात्र अथवा पुनर्विवाहित विधवा माता, तलाकशुदा/परित्यक्ता माता एवं नाता जाने वाली माता के बच्चों, विशेष योग्यजन, एच.आई.वी. अथवा कुष्ठ रोग से पीड़ित एवं मृत्युदंड/आजीवन कारावास प्राप्त माता/पिता के बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान

चर्चा में क्यों ?

10 मार्च, 2023 को राजस्थान के जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की स्कॉच अवॉर्ड डिजिटल सेरेमनी में प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है, जिसके अंतर्गत विभाग को दो पुरस्कार मिले।

प्रमुख बिंदु

- राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने ये सम्मान प्राप्त किये।
- शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएँ राज्य में ही नहीं, बल्कि देशभर में सराही जा रही हैं। अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राजस्थान देश में मॉडल स्टेट बनकर उभरा है।

नोट :

- उन्होंने बताया कि विभाग को अपने नवाचारों के लिये स्कॉच अवॉर्ड टीम द्वारा डिजिटल सर्टिफिकेट एवं साइटेशन प्रदान किया गया।
- डॉ. समित शर्मा ने बताया कि विभाग की तीन महत्त्वपूर्ण योजनाओं को ये पुरस्कार मिले। पालनहार योजना को गोल्ड अवॉर्ड, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति को सिल्वर अवॉर्ड तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को सिल्वर अवॉर्ड से नवाजा गया।
- विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर तकनीकी नवाचारों के माध्यम से योजनाओं का फायदा लाभार्थियों को पहुँचाने के लिये सुविधाओं का सरलीकरण व डिजिटलीकरण का कार्य किया जा रहा है।
- योजनाओं में ये हुए नवाचार -
  - उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में जनाधार डाटाबेस से विद्यार्थी का जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण स्वत: प्राप्त हो जाता है। कक्षा 10 एवं 12वीं की अंकतालिका सीधे ही आरबीएसई एवं सीबीएसई से ई-वॉल्ट सर्विस के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। अन्य बोर्ड की अंकतालिकाएँ डिजीलॉकर उपलब्धता के आधार पर प्राप्त की जाती हैं।
  - अनुसूचित जाति, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति सुनिश्चित करने हेतु पोर्टल पर फ्रीशिप कार्ड (विद्यार्थी को छात्रवृत्ति दिये जाने की सुनिश्चितता) का प्रावधान किया गया है।
  - पालनहार योजना में भी पेंशन योजना की तर्ज़ पर केंद्रीयकृत प्रणाली के माध्यम से निदेशालय स्तर से ही बिल बनाकर सिंगल ट्रेजरी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा, जिससे पालनहार योजना से जुड़े बच्चों को समय पर सहायता राशि का भुगतान सुनिश्चित हो सकेगा। इसके लिये मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जा चुकी है।
- शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि विभाग की तीन अन्य योजनाओं कोरोना सहायता योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को ऑडर ऑफ मेरिट सर्टिफिकेशन देकर सम्मानित किया गया है।

नोट :

जयपुर में स्थापित होगी बिहेवियरल लैब

चर्चा में क्यों ?

12 मार्च, 2023 को राजस्थान के जनसंपर्क, सूचना एवं भाषा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जयपुर ज़िले में स्थित हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में बिहेवियरल लैब की स्थापना की जाएगी। इसके लिये मुख्यमंत्री ने 22 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- बिहेवियरल लैब राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के पटेल भवन में स्थापित की जाएगी। यह देश में अत्याधुनिक तकनीक से बनाई जा रही पहली बिहेवियरल लैब होगी।
- करीब 2665.04 वर्गफीट एरिया में स्थापित होने वाली लैब का प्रबंधन एवं संचालन आईआईएम उदयपुर द्वारा किया जाएगा।
- आईआईएम उदयपुर की फैकल्टी प्रायोगिक विधियों पर प्रशिक्षण प्रदान करेगी। यहाँ पी.एच.डी. स्तर के सर्टिफिकेट कोर्स संचालित होंगे। प्रयोगों एवं कार्यशालाओं के संचालन के लिये अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा।
- यहाँ अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सहित नवीन तकनीक की मदद से मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। अत्याधुनिक लैब में फोकस ग्रुप रूम, पीसी लैब, कंट्रोल रूम फॉर मेजरमेंट, वेटिंग एरिया और ऑफिस स्पेस सहित सभी आवश्यक कक्ष बनाए जाएंगे।
- इस प्रयोगशाला के माध्यम से विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अनुभवात्मक अध्ययन आयोजित करने, शिक्षकों को प्रशिक्षण देने तथा व्यावहारिक प्रबंधन के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।

सीकर, अलवर, नागौर, भरतपुर एवं अजमेर में खोले जाएंगे पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र

चर्चा में क्यों ?

12 मार्च, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पशुपालकों को नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण दिलाने के लिये राज्य के अलवर, नागौर, भरतपुर, सीकर एवं अजमेर में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोलने और आवश्यक संसाधनों हेतु 18 करोड़ रुपए की मंज़ूरी प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- प्रस्ताव के अनुसार, राज्य के इन प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान पर हर महीने 30-30 पशुपालकों के 3 बैच होंगे। इस प्रकार एक वर्ष में कुल 36 बैच आयोजित कर 1080 पशुपालकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। इस तरह सभी पाँचों केंद्रों में प्रतिवर्ष 5400 पशुपालकों को प्रशिक्षण मिलेगा।
- राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों के सर्वांगीण विकास की दिशा में विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। प्रशिक्षण केंद्रों से उन्नत एवं समृद्ध पशुपालन की दिशा में बेहतर कार्य होंगे और रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में पाँच ज़िलों में पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की गई थी।

इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह

चर्चा में क्यों ?

11 मार्च, 2023 को राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तहत जयपुर ज़िला परिषद सभागार में ज़िला प्रशासन एवं ज़िला महिला अधिकारिता कार्यालय के तत्वावधान में ज़िलास्तरीय इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह आयोजित हुआ।

प्रमुख बिंदु

- आयोजित कार्यक्रम में महिला एवं बालिका विकास के क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं एवं शख्सियतों का सम्मान किया गया।
- समारोह में इनाया फाउंडेशन को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया, वहीं सरिता योगी को द्वितीय एवं एकादशी फाउंडेशन को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

नोट :

- सम्मानित हुई संस्थाओं और शख्सियतों को नगद पुरस्कार के साथ-साथ स्मृति चिह्न एवं प्रमाण-पत्र भी प्रदान किये गए।
- इस अवसर पर उपनिदेशक महिला अधिकारिता डॉ. राजेश डोगीवाल ने उड़ान योजना में जनजागरूकता में अहम भूमिका निभाने के लिये गरिमा शर्मा, पारुल एवं डॉ. श्रद्धा का भी सम्मान किया।
- इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग की एक साथिन, एक कार्यकर्त्ता, एक सहयोगिनी, एक सहायिका को भी 11-11 हज़ार रुपए के नगद पुरस्कार, स्मृति चिह्न एवं प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

राजस्थान मिलेट्स कान्क्लेव-2023

चर्चा में क्यों ?

13 मार्च, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के जयपुर शहर में दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव-2023 का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि कृषक कल्याण और कृषि क्षेत्र के विकास में राज्य सरकार ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। विधानसभा में दो बार पृथक् कृषि बजट पेश कर पूरे देश में ऐतिहासिक पहल की।
- उन्होंने बताया कि राज्य में मिलेट्स की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और कृषि अनुसंधान के लिये मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। लगभग 42 कृषि महाविद्यालयों की स्थापना की गई है, जिससे युवा पीढ़ी को कृषि क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण कर भविष्य सँवारने के अवसर मिल रहे हैं। हाल ही में वेटेनरी यूनिवर्सिटी की भी घोषणा की गई है।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि कृषि अनुसंधान से किसानों को भविष्य के लिये अपनी फसल तैयार करने में लाभ मिलेगा। कॉन्क्लेव में मिलेट्स का बेहतर उत्पादन, प्रबंधन और विपणन करने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सुझाव सामने आएंगे।
- इस अवसर पर उन्होंने बताया कि किसानों के लिये प्रतिमाह 2000 यूनिट नि:शुल्क बिजली उपलब्ध कराने का बजट में प्रावधान किया गया है। इससे लगभग 12 लाख किसान लाभान्वित होंगे।
- राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव-2023 में मुख्यमंत्री ने राजकिसान सुविधा एप लॉन्च किया। इसमें योजनाओं के आवेदन और उनकी स्थिति जानी जा सकेगी। इसके अलावा उन्होंने राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति-2019 की सफलता की कहानियों से संबंधित बुकलेट का विमोचन भी किया। इस दौरान 'समृद्ध किसान-खुशहाल राजस्थान'लघु फिल्म भी दिखाई गई।

नोट :

- कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हनुमानगढ़ से भूपेंद्र सिंह, नागौर से पतासी देवी, जयपुर से दिनेश कुमार चौधरी, घासीराम जाट, भीलवाड़ा से विष्णु, बाँसवाड़ा से कुरेश बागीदोरा, सीकर से हनुमानराम, अलवर से सूरजभान एवं जोधपुर से जितेंद्र सिंह सांखला को एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी (आत्मा योजना) में राज्य स्तरीय कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया।

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) के लिये 14200 करोड़ रुपए स्वीकृत

चर्चा में क्यों ?

11 मार्च, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) के निर्माण के लिये 14200 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

प्रमुख बिंदु

- 14200 करोड़ रुपए के वित्तीय स्वीकृति से नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना, निर्माणाधीन नवनेरा बैराज एवं ईसरदा बांध, रामगढ़ एवं महलपुर बैराज का निर्माण, नवनेरा बैराज, मेज एनिकट तथा गलवा बांध में पंपिंग एवं विद्युत स्टेशन स्थापित करने तथा बाढ़ के पानी को संगृहित करने सहित विभिन्न कार्य पूरे किये जा सकेंगे।
- इसके अलावा, बीसलपुर बांध की ऊँचाई 0.5 मीटर बढ़ाने तथा 202.42 कि.मी. लंबे जल परिवहन तंत्र को विकसित करने के कार्य भी किये जा सकेंगे।
- पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ई.आर.सी.पी.) के तहत वर्ष 2040 तक जयपुर, अजमेर एवं टोंक ज़िले की अतिरिक्त पेयजल आवश्यकताओं तथा जयपुर ज़िले के शेष ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 16.82 टीएमसी पेयजल की अतिरिक्त मांग को ध्यान में रखते हुए जल प्रबंधन के कार्य किये जा सकेंगे।
- उल्लेखनीय है कि पूर्वी राजस्थान के 13 ज़िलों में सिंचाई तथा पेयजल की समस्या के समाधान के लिये ई.आर.सी.पी. एक महत्त्वाकांक्षी परियोजना है। इसके तहत राज्य की नदियों में उपलब्ध अतिरिक्त पानी जो प्रतिवर्ष यमुना नदी के माध्यम से समुद्र में व्यर्थ बह जाता है, को बांधों के माध्यम से रोककर राज्य में उपयोग में लाया जाएगा।
- ज्ञातव्य है कि अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में इस परियोजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के लिये 13 हज़ार करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इसी बजट घोषणा की अनुपालना में यह स्वीकृति दी गई है।

आईटी डे-2023 फेस्टिवल

चर्चा में क्यों ?

14 मार्च, 2023 को राजस्थान जनसंपर्क, सूचना एवं भाषा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश के युवाओं का सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौशल बढ़ाने, रोज़गार सृजित करने और राज्य हित मंज़ आगामी संभावनाओं को खोजने के लिये जयपुर में राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज और जवाहर कला केंद्र परिसर में 19 से 21 मार्च तक आईटी डे-2023 का आयोजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित गतिविधियों के आयोजन के लिये 82 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।
- आईटी फेस्ट में देश के प्रसिद्ध विशेषज्ञों के बीच पैनल डिस्क्शन के साथ ही स्टार्टअप्स के लिये लाइव पिचिंग सेशन भी होंगे।
- आईटी फेस्ट में युवाओं को रोज़गार के अवसर देने के लिये संकल्पबद्ध राज्य सरकार द्वारा कॉमर्स कॉलेज परिसर में जॉब फेयर लगेगा। इसमें देशभर से नामी 400 से अधिक नियोक्ता कंपनियाँ हिस्सा लेंगी। लगभग 20 हज़ार युवाओं को रोज़गार मिलने की संभावना है। इनमें आईटी फील्ड, बीपीओ, इंजीनियरिंग, टेलीकॉम, सिविल, बैंकिंग एंड फाइनेंस, कंसल्टिंग, रिटेल, इलेक्ट्रिकल सहित मल्टी प्रोफाइल जॉब्स ऑफर किये जाएंगे।
- आईटी डे पर राजस्थान कॉलेज में 19 मार्च से 21 मार्च तक 36 घंटे का ऑफलाइन हैकाथॉन होगा। इसमें 3 हज़ार प्रतिभागी आमजन के दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान सहित राज्य और देश में विकास के लिये कई विषयों की गुत्थियों को सुलझाएंगे।

नोट :

- इसका उद्देश्य छात्रों के बीच नवाचार, समस्या-समाधान और लीक से हटकर सोचने की संस्कृति विकसित करना है। साथ ही एक लाख से अधिक प्रतिभागियों के बीच ऑनलाइन हैकाथॉन 19 मार्च से 20 मार्च तक होगा।
- इसमें विजेता को 25 लाख रुपए, द्वितीय विजेता को 20 लाख रुपए और तृतीय विजेता को 15 लाख रुपए के पुरस्कार मिलेंगे।
- जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में 'स्मार्ट विलेज' बनाया जाएगा। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की आदर्श रूपरेखा, कृषि यंत्र, ड्रोन, स्प्रिंकलर सिस्टम, जीआईएस, वाटरशेड, डिजिटल ट्रांसजेक्शन, ई-मित्र, ई-मित्र प्लस मशीन सहित स्मार्ट विलेज की अवधारणा को पूरा करने वाले सभी तकनीकें देखने को मिलेंगी। यहाँ बच्चों के लिये 7डी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी आधारित गतिविधियाँ होंगी।
- राज्य सरकार द्वारा आईटी डे इवेंट में स्टार्टअप/आईटी एक्सपो एंड बाज़ार भी लगाया जाएगा। इसमें देशभर के नामी स्टार्टअप्स अपने उत्पाद को प्रदर्शित कर उनकी बिक्री भी कर सकेंगे। यहाँ से युवाओं को नए स्टार्टअप की शुरुआत करने के लिये सीखने को भी मिलेगा।
- जवाहर कला केंद्र में यूथ फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भी होगा, जिसमें राजस्थान सहित देशभर की विभिन्न शॉर्ट, डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी।

प्रदेश में संरक्षित वन क्षेत्र बढ़कर हुआ 3.92 प्रतिशत

चर्चा में क्यों ?

15 मार्च, 2023 को राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने बताया कि वर्ष 2018 में राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91 प्रतिशत क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत था, जो वर्तमान में बढ़कर 3.92 प्रतिशत हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने बताया कि विधानसभा ने वन एवं पर्यावरण विभाग की 16 अरब 78 करोड़ 24 लाख 36 हज़ार रुपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी है।
- उन्होंने बताया कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.7 प्रतिशत वन क्षेत्र है। सरकार द्वारा नई वन नीति का अनुमोदन कर 20 प्रतिशत भूमि को वन अच्छादित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- वन मंत्री ने अवगत कराया कि वर्ष 2022-23 में 56 हज़ार 410 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया जा चुका है तथा वर्ष 2023-24 में विभिन्न विभागीय योजनाओं में 80 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया जाएगा।
- हेमाराम चौधरी ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 9 नये कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित किये गए हैं। रणथम्भौर, सरिस्का एवं मुकुंदरा टाइगर हिल्स के बाद रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा धौलपुर में एक टाइगर रिज़र्व को अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
- उन्होंने बताया कि वन क्षेत्रों के बाहर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिये ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों तथा जन सहयोग से 'ट्री आउट साइड फोरेस्ट इन राजस्थान' नाम से वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जाएगा।
- इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5 करोड़ पौधे तैयार कर वितरित किये जाएंगें।
- वन मंत्री ने बताया कि राज्य के प्रत्येक ज़िले में एक लव कुश वाटिका विकसित की जा रही है तथा वर्ष 2023-24 में हर ज़िले में एक-एक लव कुश वाटिका और विकसित की जाएंगी। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में आगामी वर्ष में 32 करोड़ रुपए के कार्य कराकर ग्रीन लंग्स क्षेत्र विकसित किये जाएंगे।
- उन्होंने बताया कि राज्य के टाइगर रिज़र्वों से ग्रामों के स्वैच्छिक विस्थापन कार्य को भी गति प्रदान की गई है। सरिस्का टाइगर रिजर्व व मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व से तीन-तीन गाँव तथा रणथम्भौर टाइगर रिज़र्व से एक गाँव पूर्णतया विस्थापित कर दिये गए है।
- हेमाराम चौधरी ने बताया कि राज्य में वन्य जीव प्रेमियों, संस्थाओं तथा कोऑपरेटिव संस्थाओं द्वारा जैविक उद्यानों में वास करने वाले वन्य जीवों को गोद लेने के लिये केपेटिव एनिमल स्पोंसर स्कीम प्रारंभ की गई है।
- उन्होंने बताया कि राज्य के संरक्षित क्षेत्रों हेतु 24 स्थानों में से 15 क्षेत्रों को इको सेंसेटिव ज़ोन के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है।
- वर्ष 2023-24 में फ्राँस सरकार के सहयोग से राज्य के 13 ज़िलों में 1 हज़ार 693 करोड़ की राजस्थान मानविकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की जाएगी तथा जाइका के सहयोग से एक हज़ार 803.42 करोड़ रुपए की एक परियोजना राज्य के 19 ज़िलों के लिये तैयार की जा रही है।

नोट :

पशुपालक सम्मान समारोह

चर्चा में क्यों ?

15 मार्च, 2023 को राजस्थान पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. भवानी सिंह राठौड़ ने बताया कि विभाग द्वारा प्रति वर्ष चयनित प्रगतिशील पशुपालकों को सम्मान देने के क्रम में इस वर्ष पशुपालक सम्मान समारोह 22 मार्च को दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- निदेशक डॉ. भवानी सिंह राठौड़ ने बताया कि राज्य के कुल चयनित 415 पशुपालकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर राज्य भर से पशुपालक भाग लेंगे।
- बैठक में आयोजन सचिव डॉ. पी.सी.भाटी ने कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में उपस्थित पशुपालकों को विषय विशेषज्ञों द्वारा विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
- साथ ही इस मौके पर पशुपालक संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत पशुपालकों को पशुपालन में आ रही समस्याओं पर चर्चा की जाएगी।

भारत सिंगापुर के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास 'बोल्ड कुरुक्षेत्र' जोधपुर में संपन्न

चर्चा में क्यों ?

06-13 मार्च, 2023 तक भारतीय सेना और सिंगापुर की सेना के बीच जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में द्विपक्षीय अभ्यास 'बोल्ड कुरुक्षेत्र'का 13वाँ संस्करण संपन्न हुआ।

प्रमुख बिंदु

- युद्धाभ्यास की श्रृंखला में पहली बार दोनों देशों की सेनाओं ने एक कमांड पोस्ट अभ्यास में भाग लिया, जिसमें बटालियन और ब्रिगेड स्तर की योजना बनाने वाली इकाईयाँ और कंप्यूटर वॉरगेमिंग शामिल थे। भारतीय सेना द्वारा आयोजित इस अभ्यास में 42वीं बटालियन, सिंगापुर आर्म्ड रेजिमेंट और भारतीय सेना की एक आर्म्ड ब्रिगेड के सैनिक शामिल थे।
- इस संयुक्त प्रशिक्षण ने उभरते हुए खतरों और उभरती प्रौद्योगिकियों के वातावरण में मैकेनाइज्ड युद्ध की आम समझ को बढ़ावा दिया, साथ ही एक जॉइंट कमांड पोस्ट के माध्यम से नियंत्रित संयुक्त अभियान और सामरिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके एक कंप्यूटर सिमुलेशन-आधारित वॉरगेम के माध्यम से अंतर-संचालन क्षमता विकसित की।
- दोनों टुकड़ियों ने न केवल एक-दूसरे के सैन्य अभ्यास और प्रक्रिया के बारे में सीखा, बल्कि आधुनिक युद्ध क्षेत्र में अपनाए जा रहे आइडिया और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान भी किया।
- उल्लेखनीय है कि युद्धाभ्यास 'बोल्ड कुरुक्षेत्र'सिंगापुर सेना और भारतीय सेना के बीच संयुक्त सेना प्रशिक्षण और अभ्यास के लिये द्विपक्षीय व्यवस्था के दायरे में आयोजित किया जाता है। पहली बार 2005 में आयोजित यह अभ्यास दोनों देशों के बीच मज़बूत और लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को रेखांकित करता है और दोनों सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाता है।

16 ज़िलों के 8 हज़ार 108 ग्राम अभावग्रस्त घोषित

चर्चा में क्यो ?

16 मार्च, 2023 को राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर 16 ज़िलों के 8 हज़ार 108 ग्राम अभावग्रस्त घोषित कर दिये। यह अधिसूचना 31 मार्च, 2023 तक लागू रहेगी।

प्रमुख बिंदु

- ज़िला कलेक्टरों से प्राप्त खरीफ फसल 2022 (संवत 2079) नियमित एवं विशेष गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर बाढ़ से फसल खराब होने पर किसानों को राहत प्रदान करने के लिये इन ज़िलों के ग्रामों के लिये के लिये अधिसूचना जारी की गई है।

नोट :

- आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार झालावाड़ ज़िले के 1597 ग्राम, बारां के 1231, भरतपुर के 957, कोटा के 766, बाँसवाड़ा के 717 तथा टोंक ज़िले के 716 ग्रामों को राहत प्रदान की गई है।
- इसी प्रकार प्रतापगढ़ ज़िले के 625, बूंदी के 517, नागौर के 347, उदयपुर के 274, अजमेर के 227, धौलपुर के 58, जोधपुर के 47, सवाई माधोपुर के 14, करौली के 13 तथा श्रीगंगानगर के 02 ग्रामों को राहत प्रदान की गई है।

राजस्थानी भाषा को राजभाषा का दर्जा देने हेतु समिति का गठन

चर्चा में क्यो ?

16 मार्च, 2023 को राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने विधानसभा में कहा कि राजस्थानी भाषा को राजस्थान की द्वितीय राजभाषा घोषित करने के संबंध में भाषा राज्यमंत्री ने एक समिति के गठन का अनुमोदन किया है।

प्रमुख बिंदु

- शिक्षा मंत्री ने बताया कि यह समिति छत्तीसगढ़ एवं झारखंड के मॉडल का अध्ययन कर वहाँ की तर्ज पर राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- विदित है कि शिक्षा मंत्री विधानसभा में शून्यकाल के दौरान सदस्य राजेंद्र राठौड़ द्वारा राजस्थानी भाषा को राज्य की राजभाषा बनाने एवं तृतीय भाषा के रुप में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जोड़ने के संबंध में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे।
- उन्होंने कहा कि वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत पाठ्यक्रम में राजस्थानी भाषा साहित्यिक विषय के रुप में शामिल है। उन्होंने कहा कि सक्षम स्तर से अनुमोदन के बाद इसे तृतीय भाषा के रुप में शामिल किया जाना संभव होगा।
- डॉ. कल्ला ने बताया कि राजस्थानी भाषा को मान्यता देने एवं संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करवाने के संबंध में राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2003 को सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया था।
- राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किये जाने के लिये केंद्र सरकार से समय-समय पर आग्रह किया जाता रहा है। इस संबंध में वर्ष 2009, 2015, 2017, 2019, 2020 व 2023 में मुख्यमंत्रियों द्वारा केंद्र सरकार को निवेदन किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रकरण भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।
- शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि विभिन्न राज्यों में अलग-अलग भाषाओं को राजभाषा बनाया गया है। वर्तमान में राज्य में राजस्थान राजभाषा अधिनियम-1956 लागू है। राजस्थानी भाषा को राजभाषा में सम्मिलित करने के लिये उक्त अधिनियम में संशोधन हेतु प्रकरण का परीक्षण करवाया जा रहा है।
- उन्होंने कहा कि महापात्रा समिति ने भी राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिये पात्र माना है। डॉ. कल्ला ने कहा कि इस संबंध में पक्ष-विपक्ष के सदस्यों को एकजुट होकर प्रधानमंत्री से मिलकर आग्रह करना चाहिये।

राजस्थान में 19 नए ज़िले, 3 नए संभाग बनेंगे

चर्चा में क्यो ?

17 मार्च, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के प्रत्युत्तर के दौरान प्रदेश में 19 नए ज़िले तथा 3 नवीन संभाग बनाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के पश्चात् अब राज्य में 50 ज़िले और 10 संभाग हो गए हैं।
- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना-कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, केकड़ी, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल, नीम का थाना, फलौदी, सलूंबर, सांचोर एवं शाहपुरा को ज़िला बनाने की घोषणा की गई। साथ ही उन्होंने बाँसवाड़ा, पाली एवं सीकर को संभाग बनाने की घोषणा की।
- जयपुर ज़िले से अलग कर जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, दूदू और फलौदी ज़िला बनाया गया है।

नोट :

- जोधपुर ज़िले से अलग कर जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम और कोटपूतली-बहरोड़ ज़िला बनाया गया है।
- इसी तरह श्री गंगानगर से अनूपगढ़, बाड़मेर से बालोतरा, अजमेर से ब्यावर और केकड़ी, भरतपुर से डीग, नागौर से डीडवाना-कुचामन सिटी, सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी, अलवर से खैरथल, सीकर से नीम का थाना, उदयपुर से सलूंबर, जालोर से सांचोर और भीलवाड़ा से अलग कर शाहपुरा को नया ज़िला बनाया गया है।
- गौरतलब है कि नए ज़िलों की घोषणा 15 साल बाद की गई है। इससे पहले 26 जनवरी, 2008 को प्रतापगढ़ राजस्थान का 33वाँ ज़िला बना था। वहीं संभाग मुख्यालय की आखिरी घोषणा 18 साल पहले 2005 को हुई थी। 4 जून, 2005 को राजस्थान का 7वाँ संभाग भरतपुर को बनाया गया था।

मुख्यमंत्री द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ

चर्चा में क्यो ?

17 मार्च, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के प्रत्युत्तर के दौरान मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत प्रथम चरण में रक्षाबंधन पर्व से 40 लाख महिलाओं को नि:शुल्क स्मार्टफोन देने सहित कई महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 19 नए ज़िले तथा 3 नवीन संभाग बनाने की घोषणा की।
- मुख्यमंत्री द्वारा की गई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएँ-
  - महाकाल उज्जैन की तर्ज पर 100 करोड़ रुपए की लागत से गोविंद देव जी मंदिर, जयपुर का विकास किया जाएगा।
  - तीर्थराज पुष्कर के समग्र विकास हेतु पुष्कर विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।
  - बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर के आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे।
  - केंद्र की सौभाग्य योजना समाप्त होने पर घरेलू विद्युत कनेक्शन से वंचित रहने वाले 2 लाख परिवारों को 1000 करोड़ रुपए की लागत से घरेलू कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे।
  - जल जीवन मिशन के तहत उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमंद ज़िलों के 8 कस्बों तथा 1473 गाँवों के 3 लाख परिवारों को 4674 करोड़ रुपए की लागत से हर घर जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे।
  - प्रदेश के आदिवासी एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले राजस्व गाँवों को डामर सड़कों से चरणबद्ध रूप से जोड़ा जाएगा।
  - आगामी वर्ष में 75 करोड़ रुपए की लागत से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिये ब्रिज कोर्स संचालित किये जाएंगे, ताकि कोरोनाकाल के दौरान हुए शैक्षणिक नुकसान की भरपाई की जा सके। इससे 70 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे।
  - स्कूली शिक्षा की सुविधा सुलभ कराने की दृष्टि से 500 प्राथमिक विद्यालयों का उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा 500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन करने की घोषणा की गई। 400 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि संकाय/विषय प्रारंभ किये जाएंगे।
  - शिक्षा विभाग की तर्ज पर मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को 2 सेट नि:शुल्क यूनीफॉर्म उपलब्ध करवाए जाएंगे तथा साथ ही, 6843 शिक्षा अनुदेशक (मदरसा पैराटीचर्स) भर्ती किये जाएंगे।
  - कार्मिकों को मई 2023 से सेवानिवृत्ति के दिन ही समस्त पेंशन परिलाभों की स्वीकृति जारी की जाएगी। 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को पेंशन राशि में मूल वेतन पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अलाउंस दिया जाएगा।

जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

18 मार्च, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नई दिल्ली के बीकानेर हाउस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का उद्घाटन किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में देश-विदेश से कला से संबंधित सभी क्षेत्रों के कलाकार शामिल हुए हैं। फेस्टिवल में नाटकों के प्रदर्शन के साथ-साथ प्रतिदिन नाट्य कला पर मंथन भी होगा। इनके माध्यम से नए कलाकार इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को सुनकर उनके अनुभवों से लाभान्वित एवं प्रेरित हो सकेंगे।
- राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बोराणा ने बताया कि जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल में देश-विदेश के 6 नाटकों का प्रदर्शन किया जाएगा।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। राज्य में उच्च शिक्षण संस्थानों में नाट्य विभाग खोलकर युवा पीढ़ी को इस कला से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही, दिल्ली में बीकानेर हाउस के द्वारा भी कलाकारों को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध करवाया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिये प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बजट में लोक कलाकार संबल कोष के गठन के लिये 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कलाकारों को यंत्र खरीदने के लिये 5000 रुपए देने तथा साल में 100 दिन काम देने के लिये योजना लाई गई है।
- इसके अलावा कोरोना काल में कलाकारों को संबल देने के लिये 5000 रुपए की सम्मान राशि उपलब्ध करवाई गई। राज्य सरकार द्वारा आयोजित लोक उत्सवों में कलाकारों को कला प्रदर्शन का अवसर दिया जा रहा है।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जोधपुर इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल पर पुस्तिका का विमोचन भी किया।

जामडोली में खुलेगा दिव्यांगजनों के लिये प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय

चर्चा में क्यों ?

20 मार्च, 2023 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि राज्य विधानसभा ने दिव्यांगजन के लिये उच्च शिक्षण एवं अनुसंधान के लिये जयपुर के जामडोली में बाबा आम्टे दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना के विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि 72 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस विश्वविद्यालय के लिये ज़मीन चिह्नित की जा चुकी है।
- उन्होंने बताया कि बाबा आम्टे दिव्यांग विश्वविद्यालय दिव्यांगजनों के लिये प्रदेश का पहला एवं देश का तीसरा विश्वविद्यालय होगा।
- इस विश्वविद्यालय की स्थापना से दिव्यांगजनों को उच्च अध्ययन एवं शोध के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। विश्वविद्यालय स्थापित करने का उद्देश्य शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के साथ ही दिव्यांगजनों का पुनर्वास कर उन्हें सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाना है।
- यह विश्वविद्यालय पूर्णतया आधुनिक होगा, जिसमें वाई-फाई, स्मार्ट क्लास रुम, मॉडर्न कंप्यूटर लैब, प्रोजेक्टर इत्यादि की सुविधा उपलब्ध होगी। विश्वविद्यालय का भवन दिव्यांगों की सुविधा को देखते हुए पूर्णतया बाधारहित बनाया जाएगा।
- मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि विश्वविद्यालय में बी.एड. बौद्धिक दिव्यांगता, डिप्लोमा इन साइन लैंग्वेज इत्यादि पाठ्यक्रम के साथ-साथ नियमित पाठ्यक्रम भी संचालित किये जाएंगे। पाठ्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2023-24 से होगी तथा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु दिव्यांग छात्र-छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

राजस्थान एमएसएमई एक्ट-2023 विधेयक पारित

चर्चा में क्यों ?

20 मार्च, 2023 को राजस्थान के उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि राज्य विधानसभा में राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) (संशोधन) विधेयक, 2023 को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि राजस्थान एमएसएमई एक्ट-2023 विधेयक आने के बाद राज्य का आर्थिक, सामाजिक स्वरूप बदलेगा और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र मजबूत होगा।
- इस अधिनियम में अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने और राज्य सरकार के विभिन्न अनुमोदन प्राप्त करने के लिये छूट की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का विनिश्चय किया गया है। एमएसएमई पॉलिसी के तहत 5 वर्ष तक किसी भी निरीक्षण या एनओसी से मुक्त उद्योग स्थापित करने का रास्ता खोला गया है।
- उन्होंने बताया कि उद्योगों से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिये राज्य स्तरीय वन स्टॉप शॉप का संचालन किया जा रहा है, जहाँ 14 विभागों के उच्च अधिकारी बैठकर उद्योगों से जुड़ी समस्याओं का तुरंत निस्तारण करते हैं।
- शकुंतला रावत ने बताया कि राजस्थान देश का पहला अनूठा राज्य है जो नई एमएसएमई और हस्तशिल्प नीति लेकर आया है।
- उन्होंने बताया कि उद्योग स्थापित करने के लिये मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, युवा उद्योग प्रोत्साहन योजना, रिप्स सहित कई प्रमुख योजनाएँ लाई गई हैं।
- प्रदेश में पहली बार ज़िला स्तर पर व्यापक रोड शो किये गए, जिससे कि छोटे से छोटा उद्यमी भी उद्योगों के लिये मिल रही छूट का लाभ उठा सका।
- विदित है कि राजस्थान में होटल को भी उद्योग का दर्जा दिया गया है। हाल ही हुए इन्वेस्ट राजस्थान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए एमओयू को धरातल पर उतारा जा चुका है।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना'

चर्चा में क्यों ?

20 मार्च, 2023 को राजस्थान के अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने राज्य के अल्पसंख्यकों के समावेशी विकास के लिये नवाचार करने की कड़ी में भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास के लिये 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना'का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना'का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को अंग्रेजी के साथ फ्रेंच, जर्मन, अरबी, स्पेनिश, फारसी और अन्य विदेशी भाषाओं का अध्ययन, बोलना व संप्रेषण कौशल विकसित कर रोज़गार प्राप्ति में सहयोग प्रदान करना है।
- भाषा के इल्म के साथ, इस योजना में नामांकित छात्रों को उनकी उपस्थिति के आधार पर 1500 रुपए मासिक अधिकतम कुल 4500 रुपए स्टाइपेंड 3 माह तक प्रदान किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि कार्यकारी एजेंसी द्वारा सभी ज़िला मुख्यालयों पर अंग्रेजी भाषा के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। अन्य विदेशी भाषाओं के प्रशिक्षण की सुविधा संभाग स्तर पर उपलब्ध है।
- 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना'राजस्थान के मूल निवासी अल्पसंख्यक समुदाय के उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षित युवाओं की ओर लक्षित है, जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच है। पात्रता के लिये लाभार्थी के परिवार/अभिभावक की वार्षिक आय 8.00 लाख रुपए तक अथवा उससे कम होना अनिवार्य है।
- अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने बताया कि 'मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक भाषा दक्षता एवं संप्रेषण कौशल विकास योजना'अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को आधुनिक दुनिया में सशक्त और सफल बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। विदेशी भाषा सीखने से उन्हें न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी बेहतर रोज़गार के अवसर मिलेंगे।

नोट :

राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 पारित

चर्चा में क्यों ?

21 मार्च, 2023 को राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादीलाल मीणा ने बताया कि राज्य विधानसभा ने राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादीलाल मीणा ने बताया कि राज्य सरकार ने सभी सदस्यों के सुझाव के आधार पर इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा था। विधेयक में सभी सदस्यों एवं चिकित्सकों के सुझाव शामिल किये गए हैं।
- उन्होंने बताया कि राज्य में अस्पतालों में उपचार के लिये मरीजों को मना नहीं किया जाए, इसीलिये राइट टू हेल्थ विधेयक लाया गया है। इसके अंतर्गत इमरजेंसी में इलाज का खर्चा संबंधित मरीज द्वारा वहन नहीं करने की स्थिति में पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
- राइट टू हेल्थ विधेयक के तहत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण लॉजिस्टिकल शिकायत का भी गठन किया गया है। साथ ही, ज़िला स्तरीय प्राधिकरण का प्रावधान भी किया गया है।
- मंत्री ने बताया कि बड़े अस्पतालों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर ज़मीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। इन अस्पतालों को राइट टू हेल्थ विधेयक के अंतर्गत जोड़ने का प्रावधान है।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल स्टेट बन रहा है। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र पर 7 प्रतिशत बजट व्यय हो रहा है।

राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 संशोधित रूप में पारित

चर्चा में क्यों ?

21 मार्च, 2023 को राजस्थान के विधि एवं विधिक कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने बताया कि राज्य विधानसभा ने अधिवक्ताओं के विरूद्ध हिंसा को रोकने के लिये राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 को संशोधित रूप में पारित कर दिया है, जिसमें अधिवक्ताओं द्वारा दिये गए महत्त्वपूर्ण सुझावों को शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- शांति कुमार धारीवाल ने बताया कि राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 राज्य में कर्तव्यों के निर्वहन करने के दौरान किसी अधिवक्ता के विरूद्ध हमला, घोर उपहति, आपराधिक बल और आपराधिक अभित्रास को रोकने के लिये लाया गया है। इस कानून से अधिवक्ताओं को हिंसा के विरूद्ध संरक्षण मिलेगा।
- उन्होंने बताया कि राजस्थान पहला राज्य है जहाँ अधिवक्ताओं के संरक्षण की दिशा में ऐसा कानून लाया गया है। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए बार काउंसिल को दिये जाते हैं।
- विधेयक के प्रावधानों को अधिवक्ताओं से विस्तृत चर्चा के बाद तैयार किया गया है। इस संबंध में वर्ष 2019 में प्रथम बैठक की गई थी, जिसके बाद कई अनौपचारिक बैठक कर विधेयक को तैयार किया गया।
- यदि कोई अपराधी किसी अधिवक्ता की संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है तो न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि उससे वसूल कर पीड़ित अधिवक्ता को देने का प्रावधान किया गया है। क्षतिपूर्ति की इस राशि की त्वरित वसूली भू-राजस्व के बकाया की तर्ज पर की जाएगी।
- अधिवक्ताओं द्वारा इस कानून का दुरुपयोग करने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही, राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, 2023 प्रारूप के खंड 9 को विलोपित कर दिया गया है।

नोट :

राज्य में 44 वेटलेंड्स के लिये ड्राफ्ट अधिसूचना जारी

चर्चा में क्यों ?

22 मार्च, 2023 को विश्व जल दिवस के अवसर पर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वेटलेंडस् की महत्ता को देखते हुए राज्य के विभिन्न ज़िलों में 44 वेटलेंड्स को चिह्नित कर आद्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की गई है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य में 44 जल संरचनाओं को वेटलेंड्स के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन वेटलेंड्स के संबंध में कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव अथवा आपत्तियाँ 60 दिन के अंदर संयुक्त शासन सचिव, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को दे सकेगा। इस अवधि में प्राप्त सुझावों एवं आपत्तियों के आधार पर इन 44 वेटलेंड्स के संबंध में अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।
- पर्यावरण एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि अधिसूचना में वेटलेंड की सीमा तथा बफर क्षेत्र का GPS विवरण देने के साथ वेटलेंड की सीमा और बफर क्षेत्र में प्रतिबंधित एवं विनियमित गतिविधियों की सूची संलग्न की गई है।
- वेटलेंड्स की सीमा में खनन कार्य, वाणिज्य कार्यों के लिये पानी का निकास, अपशिष्ट डालना, औद्योगिक गतिविधियाँ, पोचिंग, काश्तकारी इत्यादि को निषेध किया गया है।
- ज्ञातव्य है कि वेटलेंडस् जंतु ही नही बल्कि पादपों की दृष्टि से भी एक समृद्ध तंत्र हैं, जहाँ उपयोगी वनस्पतियाँ एवं औषधीय पौधे भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं तथा इनके उत्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- वेटलेंडस् बाढ़ के दौरान जल के आधिक्य का अवशोषण करते हैं जिससे मानवीय आवास क्षेत्रों में जान व माल की हानि नहीं होती। ये क्षेत्र 'कार्बन अवशोषण'व 'भू-जल स्तर में वृद्धि'जैसी महत्त्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन कर पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान देते हैं। स्थानीय लोगों की आजीविका के लिये भी वेटलेंड्स अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

'राजीव गांधी जल संचय योजना (आरजीजेएसवाई)' का द्वितीय चरण प्रारंभ

चर्चा में क्यों ?

22 मार्च, 2023 को राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री रमेश चंद मीना ने विश्व जल दिवस के अवसर पर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 'राजीव गांधी जल संचय योजना (आरजीजेएसवाई)' के द्वितीय चरण का वर्चुअल शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- राजीव गांधी जल संचय योजना (आरजीजेएसवाई) के द्वितीय चरण के अंतर्गत राज्य के 33 ज़िलों की 349 पंचायत समितियों में 2600 करोड़ रुपए की राशि से 4600 गाँवों में जल संग्रहण एवं संरक्षण के 2 लाख कार्य किये जाएंगे।
- मंत्री रमेश चंद मीना ने कहा कि ग्रामीणों को नदियों की सेंटर लाइन तय करने, लुप्त हो चुकी नदियों के पुनर्जीवन के लिये प्रयास करने, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने, खेती के लिये जैविक खाद का उपयोग करने तथा रास्तों से अतिक्रमण हटा कर जलाशयों में पानी की पहुँच सुनिश्चित करने में सहयोग करना चाहिये।
- उन्होंने बताया कि राजीव गांधी जल संचय योजना (आरजीजेएसवाई) की सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब इसमें किये जा रहे कार्य धरातल पर न सिर्फ नज़र आएँ, बल्कि क्षेत्र का जलस्तर भी बढ़े। जल संरक्षण कार्यों के संबंध में हर ग्राम सभा में चर्चा होनी चाहिये एवं आपसी विचार विर्मश के बाद ही जल संग्रहण के काम तय होने चाहिये।
- कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री द्वारा विभाग के यूट्यूब चैनल, विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल्स की लॉन्चिंग के साथ ही जलग्रहण क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिये ज़िला स्तर, ब्लॉक स्तर, परियोजना स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पुरस्कार प्रदान किये गए।
- इस अवसर पर राजीव गांधी जल संचय योजना प्रथम चरण व जलग्रहण कार्यों की महत्ता पर एक लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश को सूखे की स्थिति और अकाल से उबारने के लिये 20 अगस्त, 2019 को 'राजीव गांधी जल संचय योजना'प्रारंभ की गई। योजना के माध्यम से पुराने कुओं, नाले, नदियों, जलाशयों एवं नहरों का जीर्णोद्धार एवं उनमें जल संवर्द्धन क्षमता में वृद्धि हेतु कार्य योजना बनाकर सफाई की जा रही है। योजना के प्रथम चरण में 1450 ग्राम पंचायतों में 4029 गाँव शामिल किये गए हैं।

नोट :

चार दिवसीय संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का हुआ शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

23 मार्च, 2023 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित चार दिवसीय संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करते हुए प्रदेश में संभाग स्तरीय आरोग्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है।
- उन्होंने बताया कि 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना' के ज़रिए प्रदेश के लोगों के लिये बेहतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जा रही है। योजना में अब आमजन के लिये 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर रखा गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने आमजन को स्वास्थ्य का अधिकार देते हुए 'राइट टू हैल्थ' लागू किया है।
- ज़िला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर ने बताया कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिये आरोग्य मेले जैसे कदमों से आयुर्वेद के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा।
- आयुर्वेद विभाग के उप निदेशक राजेंद्र सिंह ने बताया कि मेले में जयपुर संभाग के सभी ज़िलों से 179 चिकित्सा अधिकारियों व 179 कंपाउडर व नर्सों ने भाग लिया।
- इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने संभाग स्तरीय आरोग्य मेले में ग्रीन हाउस औषधीय पादप प्रदर्शनी का उद्घाटन किया तथा ग्रीन हाउस में हडजोड, तुलसी, वासा, हारसिंगार, घृत कुमारी, आँवला, अंजीर, अर्जुन, वरूण, शिग्रु, गिलॉय सहित विभिन्न औषधीय पौधों की जानकारी साझा की।
- संभाग स्तरीय आरोग्य मेले में ओपीडी की 16 स्टॉल व 15 मेडिकल स्टोर की स्टॉल लगाई गई है, जिसमें हौम्योपैथी चिकित्सा परामर्श, यूनानी चिकित्सा, अग्नि कर्म चिकित्सा, शल्य (क्षारसूत्र) चिकित्सा, जलोका चिकित्सा, पंचकर्म चिकित्सा, जरावस्था चिकित्सा ओपीडी शामिल हैं।
- मेले में विशेष रूप से राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर की स्टॉल भी लगाई गई जिस पर आयुर्वेद पद्धति की ब्रोशर व पम्पलेट के ज़रिए जानकारी दी गई।

नोट :

'अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया' पर कार्यशाला

चर्चा में क्यों ?

23 मार्च, 2023 को राजस्थान की शिक्षा मंत्री जाहिदा खान ने जयपुर में 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (एनआईईपीए)' की ओर से भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वभौमीकरण के लिये शासन के अभिसरण और प्रबंधन (कनवर्जेंस एंड मैनेजमेंट फॉर यूनिवर्सेलाइजेशन एंड क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इन इंडिया) पर दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- कार्यशाला में 16 राज्यों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
- शिक्षा मंत्री जाहिदा खान ने बताया कि राजस्थान में 'प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा' (अर्ली चाईल्डहुड केयर एंड एजुकेशन-ईसीसीई) पर विशेष फोकस करते हुए कई नवाचार किये जा रहे हैं, जो देश के अन्य राज्यों के लिये अनुकरणीय है। आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूलों में समाहित करने जैसे राजस्थान के नवाचारों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शामिल किया गया है।
- उन्होंने बताया कि राजस्थान के करीब 68 हज़ार से अधिक स्कूलों में 'स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम' को लागू किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) के तहत करीब 62 हज़ार आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है, इनमें से प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों देखभाल और शिक्षा पर फोकस करते हुए 42 हज़ार से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों को शिक्षा विभाग के साथ जोड़ा जा चुका है।
- बाल्यावस्था में 1 से 6 वर्ष की आयु में बच्चों के सर्वोत्तम विकास को सबसे नाजुक माना गया है, राज्य सरकार द्वारा इस लिहाज से समय की आवश्यकता के अनुरूप ईसीसीई के महत्त्वपूर्ण घटकों की पहचान कर इस दिशा में ज़ोर-शोर से कार्य किया जा रहा है।
- राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक डॉ. मोहनलाल यादव ने बताया कि बच्चों पर आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूल और घर पर अनावश्यक मानसिक दबाव को खत्म करने के लिये राजस्थान में इस स्तर की पाठ्य पुस्तकों का संक्षिप्तीकरण करते हुए कोर्स को कम करने और शनिवार को 'नो बैग डे' जैसा नवाचार लागू करने की पहल की गई है।
- प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूलों में समाहित करते हुए अब तक 37 हज़ार से अधिक आंगनबाड़ियों में 'चाईल्ड फ्रेंडली फर्नीचर'और 34 हज़ार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिये आऊटडोर खेलों की सामग्री उपलब्ध कराई गई है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे, परफोरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स और खेलों इंडिया जैसे प्रोग्राम में राजस्थान पूरे देश में अव्वल है।
- एनआईईपीए की प्रोफेसर डॉ. रश्मिता दास ने ईसीसीई के बारे में बताया कि देश में 3 से 6 साल तक के बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार द्वारा वहन की जा रही है, जिसमें पहले निजी क्षेत्र का एकाधिकार था, इसमें सिविल सोसाईटी भी अपना योगदान दे रही है।
- पूरे देश में एक समान प्री-प्राईमरी एजुकेशन के लिये एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, जिसे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा सके।

नोट :

राजस्थान साहित्य अकादमी ने घोषित किये वर्ष 2022-23 के पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

24 मार्च, 2023 को राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर के अध्यक्ष डॉ. दुलाराम सहारण की अध्यक्षता में हुई संचालिका सभा की बैठक में राजस्थान प्रांत के निवासी एवं प्रवासी साहित्यकारों के उत्थान, संवर्धन, प्रोत्साहन और सम्मान के प्रति संकल्पबद्धता व्यक्त करने हेतु वर्ष 2022-23 के वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की गई।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में अकादमी सचिव डॉ. बसंत सिंह सोलंकी ने बताया कि वर्ष 2022-23 का मीरा पुरस्कार जयपुर के मूल निवासी एवं तिरुवनंतपुरम (केरल) वासी रति सक्सेना को कविता पुस्तक 'हँसी एक प्रार्थना'के लिये दिया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि अकादमी का पचहत्तर हज़ार रुपए की राशि वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है।
- राजस्थान सरकार के सौजन्य से प्रदान किये जाने वाला एक लाख रुपए का जनार्दन राय नागर सम्मान वर्ष 2022-23 के लिये अजमेर निवासी डॉ. चंद्र प्रकाश देवल को दिया जाएगा। गत दिनों जयपुर में हुई सम्मान समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
- वर्ष 2022-23 के वार्षिक पुरस्कारों के तहत कथा एवं उपन्यास विधा में दिया जाने वाला रांगेय राघव पुरस्कार बाँसवाड़ा निवासी भरत चंद्र शर्मा को उपन्यास 'पीर परबत-सी'के लिये दिया जाएगा।
- काव्य विधा के लिये दिया जाने वाला सुधींद्र पुरस्कार जयपुर के कवि मायामृग को कविता संग्रह 'मुझमें मीठा तू हैं'के लिये तथा एकांकी-नाटक के लिये दिया जाने वाला देवीलाल सामर पुरस्कार जयपुर निवासी अजय अनुरागी को नाट्य कृति 'रांग नंबर'के लिये घोषित किया गया है।
- आलोचना क्षेत्र का प्रतिष्ठित देवराज उपाध्याय पुरस्कार भरतपुर मूल के राजाराम भादू की आलोचना-कृति 'कविता के आयाम'को तथा विविध विधाओं के अंतर्गत कन्हैयालाल सहल पुरस्कार जयपुर के व्यंग्यकार यश गोयल को उनकी कृति 'नामुमकिन नेता'के लिये दिया जाएगा।
- बाल साहित्य के क्षेत्र का शंभूदयाल सक्सेना पुरस्कार कांकरोली की कुसुम अग्रवाल को बाल एकांकी पुस्तक 'हम सब एक हैं'के लिये दिया जाएगा।
- उक्त सभी पुरस्कार इक्कतीस हज़ार रुपए की राशि के हैं।
- सचिव डॉ. बसंत सिंह सोलंकी के अनुसार इक्कीस हज़ार रुपए की राशि वाला प्रथम प्रकाशित कृति सुमनेश जोशी पुरस्कार उदयपुर निवासी कथाकार तराना परवीन को उनके कहानी संग्रह 'एक सौ आठ'के लिये दिया जाएगा।
- बैठक में अकादमी द्वारा युवा लेखक तैयार करने की मुहिम को केंद्र में रखकर प्रारंभ किये गए विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तरीय पुरस्कारों की संचालिका से अनुमोदन पश्चात् घोषणा की गई।
- विद्यालय स्तरीय परदेशी पुरस्कार कविता के लिये महारानी गायत्री देवी कन्या विद्यालय, जयपुर की प्राची शर्मा को 'सागर मोती एवं अन्य कविताएँ'के लिये, परदेशी कहानी पुरस्कार जवाहर नवोदय विद्यालय, पल्लू-हनुमानगढ़ की दिव्या विंतामण सानप को कहानी 'खुशी के आँसू'के लिये, परदेशी निबंध पुरस्कार राउमावि अमरपुरा-उदयपुर की हर्षिता मीणा को निबंध 'नवाचारों का उद्भव'के लिये तथा परदेशी लघुकथा पुरस्कार राजकीय सार्दुल उमावि बीकानेर के अरमान नदीम की लघुकथा 'असली ताकत'के लिये दिया जाएगा।
- महाविद्यालय स्तरीय चंद्रदेव शर्मा कविता पुरस्कार राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के हिमांशु भारद्वाज को 'स्पृहा और अन्य कविताएँ'के लिये, चंद्रदेव शर्मा कहानी पुरस्कार इक्कीस कॉलेज गोपल्याण-लूणकरणसर की निर्मला शर्मा को कहानी 'कोई चारा नहीं'के लिये, चंद्रदेव शर्मा एकांकी पुरस्कार माँ जालपा देवी राजकीय महाविद्यालय तारानगर की तनिष्का पड़िहार की एकांकी 'जागो प्यारे, जागो'के लिये, चंद्रदेव शर्मा निबंध पुरस्कार सोनादेवी सेठिया कन्या महाविद्यालय सुजानगढ़ की मैना कंवर को निबंध 'विगत और संभावनाएँ'के लिये दिया जाएगा।
- सुधा गुप्ता महाविद्यालय स्तरीय कविता पुरस्कार महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय जोधपुर की सूरज कुमारी को 'प्रकृति की आवाज और अन्य कविताएँ'के लिये दिया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि उक्त सभी पुरस्कारों के तहत पाँच हज़ार रुपए प्रति पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।

नोट :

- संचालिका की बैठक में अकादमी द्वारा दिये जाने वाले विशिष्ट साहित्यकार सम्मानों की भी घोषणा की गई।
- वर्ष 2022-23 का विशिष्ट साहित्यकार सम्मान अजंता देव-जयपुर, अतुल चतुर्वेदी-कोटा, डॉ. अनिता वर्मा-कोटा, कुसुम मेघवाल-उदयपुर, कैलाश मनहर-मनोहरपुरा, गोपाल माथुर-अजमेर, गोरधनसिंह शेखावत-सीकर, जवरीमल्ल पारख-जोधपुर, जीवन सिंह मानवी-अलवर, फारूख आफरीदी-जयपुर, बख्शीश सिंह-अजमेर, डॉ. महेंद्र भानावत-उदयपुर, मालचंद तिवाड़ी-बीकानेर, राजन निर्मोही जावा-जोधपुर, डॉ. रामकुमार घोटड़-सादुलपुर, रामस्वरूप किसान-परलीका, राजेंद्र कसवाँ-झुंझुनू, रेवतीरमण शर्मा-अलवर, शिवराज छंगाणी-बीकानेर, विद्या पालीवाल-उदयपुर, डॉ. सत्यनारायण-जोधपुर, सावित्री चौधरी-जयपुर, हबीब कैफी-जोधपुर, हरिराम मीणा-बामनवास, हसन जमाल-जोधपुर को दिया जाएगा।
- इस सम्मान के तहत प्रत्यके को इक्कावन हज़ार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
- संचालिका बैठक में लिये गए कई अन्य फैसले-
  - अकादमी की 'राजस्थान साहित्यकार प्रस्तुति योजना'एवं 'पुरोधा श्रृंखला'में कई पुस्तकों का नवीन प्रकाशन होगा, वहीं लंबित समस्त पुस्तकों को भी प्रकाशित किया जाएगा।
  - वहीं कविता, कहानी, निबंध, स्त्री-विमर्श, दलित-विमर्श, आदिवासी-विमर्श, युवा साहित्य, बाल साहित्य, नाटक पर केंद्रित स्वतंत्र पुस्तकों का प्रकाशन होगा। अकादमी की पत्रिका मधुमती के गांधी विशेषांक, नेहरू विशेषांक का पुस्तकाकार में प्रकाशन भी होगा।
  - आगामी वर्ष की पुरस्कार एवं विभिन्न योजनाओं की विज्ञप्ति प्रकाशन का निर्णय भी लिया गया।

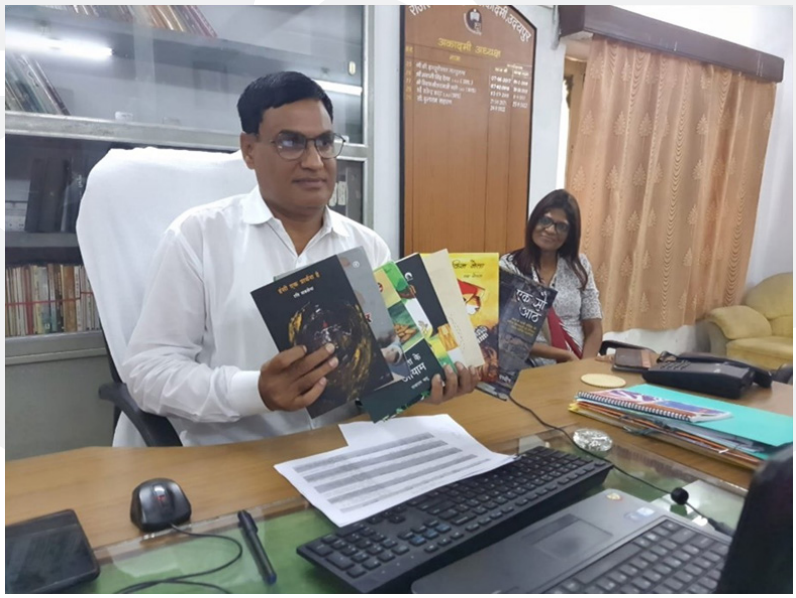

उदयपुर एवं राजसमंद में बनेंगे केटल फीड प्लांट

चर्चा में क्यों ?

24 मार्च, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के उदयपुर एवं राजसमंद के नाथद्वारा में केटल फीड प्लांट की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस निर्णय से राज्य में अधिक मात्रा में पशु आहार का उत्पादन हो सकेगा और पशुओं के लिये गुणवत्तापूर्ण आहार आसानी से उपलब्ध हो सकेगा।
- स्थापना के लिये राशि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) के माध्यम से व्यय की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा 2023-24 के बजट में केटल फीड प्लांट की स्थापना के संबंध में घोषणा की गई थी।

नोट :

राष्ट्र स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

26 मार्च, 2023 को राजस्थान के आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने राज्य के शांति और अहिंसा विभाग का दो दिवसीय राष्ट्र स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग सम्मेलन का बीकानेर के डागा पैलेस में उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री की पहल पर महात्मा गांधी के विचारों को जन-जन तक पहुँचाने के लिये देश का पहला शांति और अहिंसा विभाग राजस्थान में स्थापित किया गया है एवं इस विभाग के माध्यम से समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।
- इन कार्यक्रमों के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग के लिये कार्य करने वाले लोगों और संस्थाओं को एक-दूसरे को समझने का अवसर मिलेगा।
- राज्य भूदान यज्ञ बोर्ड के अध्यक्ष लक्ष्मण कड़वासरा ने बताया कि खादी को प्रोत्साहित करने के आंदोलन में बीकानेर की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है एवं यहां की अनेक खादी संस्थाओं ने जन-जन में देशभक्ति की भावना जगाई। बेरोज़गारी की समस्या के समाधान में खादी की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो सकती है।
- बीकानेर के ज़िला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों की 152 खादी संस्थाओं के प्रतिनिधि भागीदारी निभा रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं।
- दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिये जाएंगे।

राजस्थान साहित्य उत्सव (साहित्य कुंभ-2023) जोधपुर में शुरू

चर्चा में क्यों ?

25 मार्च, 2023 को राजस्थान के कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने तीनदिवसीय राजस्थान साहित्य उत्सव (साहित्य कुंभ-2023) के आयोजन का शुभारंभ जोधपुर के उम्मेद उद्यान स्थित जनाना बाग में किया।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने समारोह में विभिन्न अकादमियों की ओर से उल्लेखनीय कृतित्व तथा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिये 7 मनीषी विद्वानों/साहित्यकारों को विभिन्न पुरस्कारों से विभूषित किया।
- इनमें राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर की ओर से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में संस्कृत एवं प्राच्य विद्या संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर प्रमोद कुमार शर्मा को अखिल भारतीय माघ पुरस्कार तथा आयुर्वेद एवं संस्कृत के मनीषी प्रो. वैद्य बनवारी लाल गौड़ को अंबिकादत्त व्यास पुरस्कार दिया गया।
- राजस्थान उर्दू अकादमी, जयपुर की ओर से डॉ. अशरद अब्दुल हमीद (टोंक) को प्रो. महमूद शिरानी अवॉर्ड और आदिल रजा मंसूरी (जयपुर) को अख्तर शिरानी अवॉर्ड, प्रख्यात बाल साहित्यकार डॉ. दिविक रमेश (दिल्ली) एवं डॉ. प्रबोध कुमार गोविल (जयपुर) तथा कलाधर्मी एवं बहुआयामी सृजनात्मक रचनाकार चांद मोहम्मद घोसी (मेड़ता) को पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर के बाल साहित्य मनीषी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया।
- समारोह में राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से पद्मश्री चंद्रप्रकाश देवल को पं जनार्दन राय नागर पुरस्कार तथा हबीब कैफी एवं शिवराज छंगाणी को विशिष्ट साहित्यकार सम्मान प्रदान किया गया।

नोट :

बीकानेर में तीन दिवसीय किसान मेला शुरू

चर्चा में क्यों ?

27 मार्च, 2023 को राजस्थान के बीकानेर ज़िले में स्थित स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में तीन दिवसीय (27 मार्च-29 मार्च) किसान मेला प्रारंभ हुआ।

प्रमुख बिंदु

- किसान मेला 'पोषक अनाज, समृद्ध किसान' की थीम पर आयोजित किया जा रहा है।
- विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अरुण कुमार ने बताया कि मेले के दौरान केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, आईसीएआर संस्थानों, राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों तथा निजी स्टॉल धारकों की लगभग 100 प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं।
- मेले के दौरान किसानों के लिये विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित होंगी। मेले का पहला दिन फल, सब्जी और पुष्प दिवस, दूसरा दिन पशुपालन दिवस तथा तीसरा दिन फसल दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
- इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री भँवर सिंह भाटी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, किसानों को प्रतिमाह 2000 यूनिट बिजली निशुल्क उपलब्ध करवाने जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिये गए हैं।
- इस दौरान कृषि मंत्री ने विभिन्न पुस्तकों जैसे- मेला स्मारिका, मशरूम उत्पादन तकनीक, प्रगति के पथ पर अग्रसर कृषि महाविद्यालयरू मंडावा, हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ मिलेट्स फॉर एग्री एंटरप्रेन्योरशिप का विमोचन किया।
- उन्होंने आत्मा द्वारा चयनित किसानों, विभिन्न कृषक प्रतियोगिताओं के विजेताओं, चौधरी चरण सिंह स्मृति पुरस्कार के विजेताओं को पुरस्कृत किया। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र झुंझुनू के प्रभारी डॉ. दयानंद को सर्वश्रेष्ठ प्रसार कार्यकर्त्ता के रूप में सम्मानित किया।
- इस दौरान उन्होंने कृषि महाविद्यालय के स्नातकोत्तर कन्या छात्रावास और सभागार का लोकार्पण भी किया।

राज्य में अब शॉप्स एवं डॉग ब्रीडर्स का पंजीयन अनिवार्य

चर्चा में क्यों ?

27 मार्च, 2023 को राजस्थान जीव-जंतु बोर्ड के अध्यक्ष के.सी. विश्नोई ने बताया कि राज्य में पालतू जीव-जंतुओं की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिये जीव-जंतु कल्याण बोर्ड ने प्रभावी कदम उठाते हुए राज्य में संचालित डॉग ब्रीडर्स एवं पेट शॉप्स का पंजीयन जीव-जंतु कल्याण बोर्ड में करवाना अनिवार्य कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- पंजीयन के लिये राज्य में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स नियम 2017 व 2018 को लागू कर दिया गया है।
- जीव-जंतु बोर्ड के अध्यक्ष के.सी. विश्नोई ने बताया कि ऐसी पेट शॉप एवं डॉग ब्रीडर्स संस्थाएँ जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (डॉग ब्रीडिंग एवं मार्केटिंग नियम) 2017 एवं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स (पेट शॉप नियम) 2018 के अंतर्गत पंजीयन की श्रेणी में हों, को राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना अनिवार्य होगा।
- बोर्ड में रजिस्ट्रशन के उपरांत ही स्थानीय निकाय विभाग द्वारा लाइसेंस दिया जाएगा। लाइसेंस पाँच वर्ष की अवधि के लिये वैध रहेगा, तत्पश्चात् इसका नवीनीकरण करवाना होगा।
- पंजीयन प्रक्रिया के दौरान बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के द्वारा संस्था का निरीक्षण किया जाएगा व पंजीयन के पश्चात् भी समय-समय पर निरिक्षण किये जाएंगे, जिससे पालतू पशुओं की दुकानों पर ब्रीडिंग एवं उनके रख-रखाव के सबंध में गुणवत्तापूर्ण कार्य हो सकेंगे।
- जीव-जंतु बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि अब राज्य में ब्रीडर बिना पंजीयन के ब्रीडिंग का कार्य नहीं कर सकेंगे। ब्रीडर्स एवं पेट शॉप मालिक राज्य के ज़िलों के संयुक्त निदेशक कार्यालय एवं राज्य जीव-जंतु कल्याण बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं।

नोट :

प्रतापगढ़ में 'पीपलखूंट हाइलेवल कैनाल'के लिये 2000 करोड़ रुपए स्वीकृत

चर्चा में क्यों ?

28 मार्च, 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतापगढ़ ज़िले में 'पीपलखूंट हाइलेवल कैनाल' के निर्माण के लिये 2000 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इस योजना से ज़िले के 5000 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

प्रमुख बिंदु

- 'पीपलखूंट हाइलेवल कैनाल'के तहत माही बेसिन के अधिशेष जल से प्रतापगढ़ ज़िले के अनकमांड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- इस योजना से ज़िले की पीपलखूंट तहसील के पीपलखूंट, राझड़ी चौकी, टामटिया, नालचौकी, नालदा, केलामेला, बोरी, महूड़ीखेड़ा, मोरवानिया, ठेचला, सोबनिया, जेथलिया आदि गाँव लाभान्वित होंगे।
- मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से 3.72 टीएमसी अतिरिक्त सिंचाई जल उपलब्ध होने से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा क्षेत्र का विकास सुनिश्चित हो सकेगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व में 'पीपलखूंट हाइलेवल कैनाल'के निर्माण की बजट घोषणा की थी। उक्त घोषणा की क्रियान्विति में यह स्वीकृति दी गई है।

पन्नाधाय, अमरा जी भगत और केसरी सिंह बारहठ का बनेगा पेनोरमा

चर्चा में क्यों ?

28 मार्च, 2023, को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहठ, महाबलिदानी पन्नाधाय और लोकदेवता अमरा जी भगत के पेनोरमा के निर्माण के लिये 12 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की स्वीकृति से चित्तौड़गढ़ ज़िले में पन्नाधाय के पैतृक स्थल पाण्डोली में 4 करोड़ रुपए की लागत से 'पन्नाधाय पेनोरमा'बनेगा। पेनोरमा में पन्नाधाय के कृतित्व एवं व्यक्तित्व को विभिन्न माध्यमों से दर्शाया जाएगा। आमजन को उनके बलिदान, त्याग, साहस एवं स्वाभिमान की जानकारी मिलेगी।
- चित्तौड़गढ़ ज़िले में भदेसर तहसील के गाँव दौलतपुरा (ग्राम पंचायत बागुंड) में लोकदेवता अमरा जी भगत (अनगढ़ बावजी) का पेनोरमा भी 4 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। यहाँ सामाजिक सरोकार के कार्यों के बारे में जानकारी मिलेगी।
- भीलवाड़ा के शाहपुरा में स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहठ के पेनोरमा का निर्माण होगा। इसमें 4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस पेनोरमा से युवा वर्ग अपने अधिकारों के प्रति शिक्षित और जागृत होगा।
- इन तीनों ही पेनोरमा में मुख्य भवन, सभागार, हॉल, पुस्तकालय, प्रतिमा, छतरी, शिलालेख, स्कल्पचर्स, ऑडियो-वीडियो सिस्टम जैसे विभिन्न कार्य होंगे। तीनों जगह निर्माण कार्य पर्यटन विकास कोष से कराए जाएंगे।
- महाबलिदानी पन्नाधाय का जन्म चित्तौड़ के पास 'माताजी की पांडोली'नामक गाँव मे वर्ष 1501 ई. में एक गुर्जर परिवार मे हुआ था। महाराणा सांगा के पुत्र और महाराणा प्रताप के पिता उदयसिंह की रक्षा के लिये पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर संपूर्ण विश्व में अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उदयसिंह के जीवन-रक्षा के लिये पन्नाधाय की स्वामिभक्ति, चंदन के बलिदान और कीरत बारी के साहस की गाथा 'महाबलिदानी पन्नाधाय पेनोरमा'में फिर से जीवंत होगी।
- स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहठ का जन्म 21 नवंबर, 1872 को हुआ था। वे शाहपुरा क्षेत्र के देव खेड़ा के जागीरदार थे। स्वतंत्रता आंदोलन की रणनीति तय करने के लिये वे अपनी हवेली पर गुप्त मंत्रणा किया करते थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी को भी पूरा सहयोग दिया था। केसरी सिंह ने राजस्थानी में लिखे 13 सोरठे के ज़रिये भी लोगों में क्रांति का बिगुल फूँका था।
- उन्होंने युवाओं में क्रांति की अलख जगाई। उन्होंने पूरे परिवार को आज़ादी के आंदोलन में झोंक दिया। शक्ति, भक्ति और कुर्बानी की कण-कण में महान क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहठ और उनके परिवार की शौर्य गाथा देश भर में गूँजती है।

नोट :

- राजस्थान के चित्तौड़गढ़ ज़िले के बड़ी सादड़ी विधानसभा इलाके में नरबदिया तहसील के भदेसर में संत शिरोमणि अमरा भगत का समाधि स्थल है। जब संत अमरा भगत का जन्म हुआ तो उन्होंने जन्म के 9 दिन तक अपनी माँ का दूध नहीं पिया था। सूर्य पूजन की रस्म पूरी करने के बाद माँ का दूध पीने पर इस यशस्वी बालक की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। उस समय देश में प्लेग नाम की महामारी और लाल ताव के नाम की बीमारी फैली तो उन्होंने इस महामारी से बचाने के लिये अनगढ़ बावजी की धूनी पर घोर तपस्या की और लोगों को बचाया।

राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के पुरस्कारों की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

29 मार्च, 2023 को राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष शिवराज छंगाणी ने वर्ष 2022-23 के लिये अकादमी पुरस्कारों तथा सम्मानों की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- अकादमी कार्यसमिति की बैठक में अध्यक्ष शिवराज छंगाणी ने विभिन्न पुरस्कारों के निर्णायकों की संस्तुतियों के आधार पर निर्णय की जानकारी दी।
- विभिन्न पुरस्कार एवं सम्मान तथा चयनित व्यक्ति-
  - सूर्यमल्ल मीसण शिखर पुरस्कार (पद्य) (71 हज़ार रुपए) - बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार मधु आचार्य आशावादी को उनकी पुस्तक 'पीड़ आडी पाळ बाध'के लिये।
  - गणेशीलाल व्यास उस्ताद पद्य पुरस्कार (51 हज़ार रुपए) - बारां निवासी ओम नागर को उनकी पुस्तक 'बापू : एक कवि की चितार'के लिये।
  - शिवचंद भरतिया गद्य पुरस्कार (51 हज़ार रुपए) - बीकानेर के कमल रंगा को पुस्तक 'आलोचना रै आभै सोळह कलावां'के लिये।
  - मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार (51 हज़ार रुपए) - अलवर ज़िले के कलेक्टर तथा राजस्थानी व हिन्दी के चर्चित साहित्यकार डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी को उनकी पुस्तक 'भरखमा'के लिये।
  - बावजी चतर सिंह अनुवाद पुरस्कार (31 हज़ार रुपए) - लूणकरणसर के राजूराम बिजारणियाँ को उनकी पुस्तक 'झोकड़ी खावतो बगत'के लिये।
  - सांवर दइया पैली पोथी पुरस्कार (31 हज़ार रुपए) - भीलवाड़ा के मोहन पुरी को उनकी पुस्तक 'अचपळी बातां'के लिये
  - जवाहरलाल नेहरू राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार (31 हज़ार रुपए) - रायसिंहनगर की किरण बादळ को उनकी पुस्तक 'टाबरां री दुनियां'के लिये।
  - प्रेमजी प्रेम राजस्थानी युवा लेखन पुरस्कार (31 हज़ार रुपए) - लूणकरणसर के देवीलाल महिया को उनकी पुस्तक 'अंतस रो ओळमो', के लिये।
  - राजस्थानी महिला लेखन पुरस्कार (31 हज़ार रुपए) - बीकानेर की डॉ. कृष्णा आचार्य को उनकी पुस्तक 'नाहर सिरखी नारियां' के लिये।
  - रावत सारस्वत राजस्थानी साहित्यिक पत्रकारिता पुरस्कार (31 हज़ार रुपए) - 'राजस्थली' पत्रिका श्रीडूंगरगढ़ को दिया जाएगा।
- सचिव शरद केवलिया ने बताया कि भतमाल जोशी महाविद्यालय पुरस्कार के तहत प्रथम स्थान प्राप्त राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के छात्र योगेश व्यास को उनकी कहानी 'गैरी नींद'पर 11,000 रुपए का व द्वितीय स्थान प्राप्त जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र व फालना निवासी अभिमन्यु सिंह इंदा को उनके व्यंग्य 'थांरो-म्हारो भविष्य'के लिये 7,100 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
- मनुज देपावत पुरस्कार के तहत प्रथम स्थान प्राप्त राजकीय सार्दुल उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर के छात्र अरमान नदीम को उनकी लघुकथा 'खोखो नीं हटसी'पर 7,100 रुपए का व द्वितीय स्थान प्राप्त इक्कीस एकेडमी फॉर ऐक्सीलेंस गोपल्याण की छात्रा व महाजन निवासी कल्पना रंगा को उनकी कहानी 'कंवळै मन री डूंगी पीड़'पर 5,100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा।

नोट :

- इनको मिलेगा सम्मान-
  - राजस्थानी भाषा सम्मान (51 हज़ार रुपए) - वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. चंद्रप्रकाश देवल (अजमेर)
  - राजस्थानी साहित्य सम्मान (51 हज़ार रुपए) - वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. अर्जुन देव चारण (जोधपुर)
  - राजस्थानी संस्कृति सम्मान (51 हज़ार रुपए) - ब्रजरतन जोशी (बीकानेर)
  - राजस्थानी प्रवासी साहित्यकार सम्मान (51 हज़ार रुपए) - रामबक्स (मुंबई)
- अकादमी का 31,000 रुपए प्रत्येक का आगीवाण सम्मान प्रदेश के 14 वरिष्ठ साहित्यकारों को प्रदान किया जाएगा। इनमें नंदकिशोर शर्मा (जैसलमेर), मेहरचंद धामू (परलीका, हनुमानगढ़), चांदकौर जोशी (जोधपुर), दीनदयाल ओझा (जैसलमेर), सोहनदान चारण (जोधपुर), भोगीलाल पाटीदार (डूंगरपुर), भंवरलाल भ्रमर (बीकानेर), गौरीशंकर भावुक (तालछापर, सुजानगढ़), पुरुषोत्तम पल्लव (उदयपुर), श्याम जांगिड़ (चिड़ावा, झुंझुनूं), गोपाल व्यास (बीकानेर), मुकट मणिराज (कोटा), बिशन मतवाला (बीकानेर), उपेंद्र अणु (ऋषभदेव, उदयपुर) शामिल हैं।

आईसीडीएस विभाग के आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों एवं शिशुपालना गृह कायकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि

चर्चा में क्यों ?

29 मार्च, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग (ICDS) के आंगनबाड़ी केंद्रों एवं शिशुपालना गृह पर कार्यरत मानदेय कर्मियों को दिये जाने वाले मानदेय के राज्यांश में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।

प्रमुख बिंदु

- आईसीडीएस विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत मानदेय कर्मियों-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं शिशुपालना गृह कायकर्ताओं के मानदेय में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।
- वर्तमान में इन कार्मिकों को मानदेय का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में किया जा रहा है। यह वृद्धि इन कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे कुल मानदेय का 15 प्रतिशत होगी। इससे राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 70 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में मानदेय वृद्धि के लिये घोषणा की गई।

स्टेट जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की 57 वीं बैठक

चर्चा में क्यों ?

29 मार्च, 2023 को जयपुर सचिवालय में स्टेट जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की 57वीं बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राज्य माइंस विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने की।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य में योजनाबद्ध खनिज एक्सप्लोरेशन और खनिज ब्लॉकों की नीलामी के परिणामस्वरूप ही पेट्रोल-प्राकृतिक गैस की खोज व दोहन के साथ ही अब देश दुनिया के नक्शे पर जैसलमेर सीमेंट हब के रूप में विकसित होने जा रहा है।
- इसके अलावा प्रदेश में यूरेनियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लाईम स्टोन, लिग्नाइट, आयरन ओर, कॉपर, जिंक, गारनेट आदि के नित नए भंडार खोजे जा रहे हैं।
- डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2023-24 में खनिज लाईम स्टोन, फेरस मेटल, डेकोरेटिव स्टोन, औद्योगिक खनिज एवं अन्य खनिजों की खोज हेतु 31 विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से कार्य किया जाएगा तथा सेमी प्रेसियस स्टोन के भंडारों के कार्य को भी गति दी जानी है।

नोट :

- बैठक में एक्सप्लोरेशन और मेजर व माइनर ब्लॉक्स तैयार करने के कार्य में जियोलॉजी विंग के कार्यों को रेखांकित किया गया। राज्य का ध्येय ओडिशा की बेस्ट प्रेक्टिसेज का अध्ययन कराकर राज्य के लिये व्यावहारिक प्रक्रिया को अपनाना है, ताकि माइनिंग क्षेत्र में राजस्व अर्जन में भी देश का अग्रणी प्रदेश बन सके।
- विभाग द्वारा राजस्व अर्जन में भी साल दर साल प्रगति करते हुए मेजर और माइनर ब्लॉकों की अधिक से अधिक नीलामी से वैध खनन को बढ़ावा मिला है तो राजस्व और रोज़गार में बढ़ोतरी हुई है।
- निदेशक माइंस संदेश नायक ने बताया कि राज्य के आर्थिक व औद्योगिक विकास के साथ ही कृषि क्षेत्र में खनिज क्षेत्र द्वारा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। रॉक फास्फेट के विपुल भंडारों के साथ ही जिप्सम आदि से मिनरल फर्टिलाइजर तैयार हो रहे हैं, वहीं अब पोटाश के खोज कार्य को और अधिक गति दी गई है, ताकि योजनाबद्ध तरीके से पोटाश का खनन शुरू कर विदेशों से आयात पर निर्भरता कम की जा सके।
- राज्य में खनिज क्षेत्र में सराहनीय कार्य हो रहा है। जीएसआई द्वारा भी जियोफिजिकल, जियोकेमिकल, ग्राउंड जियोफिजिकल और एरो जियोफिजिकल कार्य हो रहा है। प्रदेश में बहुमूल्य खनिजों के भंडार खोजे गए हैं और खोज कार्य जारी है तथा आरएसएमईटी के सहयोग से प्रदेश में एक्सप्लोरेशन कार्य को और अधिक गति दी जा रही है।

राजस्थान दिवस 2023

चर्चा में क्यों ?

30 मार्च, 2023 को राजस्थान का 74वाँ स्थापना दिवस मनाया गया। आज ही के दिन 30 मार्च, 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर में एक समारोह में वृहद् राजस्थान का उद्घाटन किया था।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि 14 जनवरी, 1949 को उदयपुर की एक सार्वजनिक सभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर रियासतों के सैद्धांतिक रूप से विलय की घोषणा की थी।
- इस घोषणा को मूर्त रूप देने के लिये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर में 30 मार्च, 1949 को एक समारोह में वृहद् राजस्थान का उद्घाटन किया था, इसलिये राजस्थान दिवस हर वर्ष तीस मार्च को मनाया जाता है।
- आज़ादी से पहले राजस्थान को 'राजपूताना'के नाम से जाना जाता था। इतिहासकारों का मानना है कि जार्ज थॉमस ने साल 1800 ईसा में 'राजपूताना'नाम दिया था। इतिहासकारों का दावा है कि कर्नल जेम्स टॉड ने इस राज्य का नाम राजस्थान रखा। स्थानीय साहित्यिक भाषा में राजाओं के निवास प्रांत को राजस्थान ही कहा जाता था।
- आज़ादी के वक्त राजस्थान में कुल 22 रियासतें थी। वर्तमान राजस्थान में तत्कालीन 19 देसी रियासतों में राजाओं का शासन हुआ करता था। जबकि, तीन रियासतों (नीमराना, लव और कुशालगढ़) में चीफशिप थी। यहाँ के अजमेर-मेरवाड़ा प्रांत पर ब्रिटिश शासकों का राज था।
- तत्कालीन रियासतों के विलय की प्रक्रिया 18 मार्च, 1948 से एक नवंबर 1956 तक चली। इस प्रक्रिया को सात चरणों में पूरा किया गया था।
- भारत सरकार ने अफजल अली के नेतृत्व में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिश शासित अजमेर-मेरवाड़ा प्रांत का 1 नवंबर, 1956 को राजस्थान में विलय कर लिया।
- इस दौरान ही मध्य प्रदेश की मंदसौर तहसील के गाँव सुनेलटप्पा को भी राजस्थान में शामिल किया गया। जबकि, राजस्थान के झालावाड़ ज़िले के गाँव सिरोंज को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया।
- भारत सरकार की गठित राव समिति की सिफारिशों के आधार पर 7 सितंबर, 1949 को जयपुर को राजस्थान राज्य की राजधानी बनाया गया।
- राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल तीन लाख 42 हज़ार 239 वर्ग किलोमीटर है। यह देश का 1/10 भूभाग है।
- 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.89 करोड़ है, जो कि भारत की जनसंख्या का 5.66 प्रतिशत है। जनसंख्या के अनुसार ये देश में सातवें स्थान पर है।

नोट :

- राजस्थान में अभी तक सात संभाग और 33 ज़िले थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 मार्च, 2023 को दो ज़िलों का विलय करते हुए 19 नए ज़िले और तीन नए संभाग के गठन की घोषणा की। इसके बाद से अब राजस्थान में कुल 10 संभाग और 50 ज़िले हो गए हैं। हालाँकि नए ज़िलों और संभागों का नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है।
- राजस्थान पड़ोसी देश पाकिस्तान से सटा हुआ है। उसके साथ इसकी 1,070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर ज़िलों की सीमाएँ पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जैसलमेर ज़िले में कुलधरा गाँव सबसे पुराना गाँव है। माना जाता है कि यह गाँव 200 साल से वीरान है।
- राजस्थान की 4850 किलोमीटर सीमा देश के दूसरे राज्यों से मिलती है जिनमें पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात राजस्थान के सीमावर्ती राज्य हैं।
- पर्यटन के नक्शे में राजस्थान की विशेष पहचान है। यहाँ दर्जनों ऐसे पर्यटन स्थल हैं, जहाँ रोज़ाना हज़ारों की संख्या में देसी-विदेशी पर्यटक आते हैं। वहीं धोरों की धरती जैसलमेर की अपनी अलग पहचान है। वहाँ हिचकोले खाते पर्यटक ऊँटों की सवारी का आनंद लेते देखे जा सकते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर हो या पिंक सिटी जयपुर, पर्यटन की दृष्टि से यहाँ कई दर्शनीय स्थान हैं।
- राजस्थान में कई किले हैं, इनमें 13 प्रमुख हैं। इनमें जयपुर का आमेर और जयगढ़ किला, जोधपुर का मेहरानगढ़ किला, राजसमंद का कुंभलगढ़ किला, सवाई माधोपुर का रणथंभोर किला, बीकानेर का जूनागढ़ किला, भरतपुर का लोहागढ़ किले की दुनियाभर में पहचान है। अन्य किलों और महलों में गागरौन किला, जैसलमेर, सिरोही का अचलगढ़, नागौर का अहिछत्रगढ़, जालौर दुर्ग, सिरोही का खिमसर किला, अलवर का निमराणा किला, सिटी पैलेस आदि भी प्रसिद्ध हैं। अभेद्या किलों के साथ रानियों के रहने के लिये आलीशान महल भी बने हुए थे।
- राजस्थान, पृथ्वी राज चौहाण, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा जैसे शूरवीरों के इतिहास को सहेजे हुए है। देश-दुनिया में राजस्थान को वीरों की धरती से ही पहचाना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध, चित्तौड़, खानवा, तराइन, रणथंभौर के युद्ध राजस्थान की धरती पर ही हुए।
- वर्तमान समय में भारतीय सेना में राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र (सीकर, झुंझुनू और चूरू) से बड़ी संख्या में युवा हैं। देश सेवा के लिये राजस्थान के शेखावाटी से सर्वाधिक युवा सेना में जाते हैं।

नोट :

जोधपुर में सूचना आयोग की बेंच स्थापित होगी

चर्चा में क्यों ?

30 मार्च, 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये जोधपुर में सूचना आयोग की बेंच स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यालय के संचालन के लिये 12 नवीन पदों तथा आवश्यक वित्तीय प्रावधान की भी स्वीकृति दी है। इन नवीन पदों में एक पद सूचना आयुक्त का है, जिसकी नियमानुसार नियुक्ति की जाएगी।
- इसके अलावा निजी सहायक, रीडर, सूचना सहायक का एक-एक पद, वरिष्ठ सहायक के 2 पद तथा कनिष्ठ सहायक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 3-3 पद शामिल हैं।
- सूचना आयोग की बेंच के लिये आवश्यक संसाधन आदि के लिये भी 20 लाख रुपए स्वीकृत किये गए हैं।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में बेंच की स्थापना के लिये घोषणा की गई थी।

दृष्टि The Vision

नोट :